# मंजरी

स्त्री के मन की

जनवरी, 2015 अंक 3

## गंदगी कितनी महंगी

हमारी बात

# मंजरी : स्त्री के मन की

संरक्षण

डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर, समाज शास्त्र, पटना विवि

प्रोफेसर डेजी नारायण
प्रोफेसर, इतिहास, पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

कीर्ति
परियोजना प्रबंधक, महिला सामाख्या, बिहार

डा. शरद कुमारी
समाज सेविका

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
लेखिका

भारत की आधी जनसंख्या खुले में शौच करती है। यह पंक्ति देश के गरीबों तक सफाई के मौलिक सुविधाओं को भी न पहुंचा पाने की अक्षमता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं और हरियाणा के भगाना में हुए बर्बर बलात्कारों में एक चीज जो समान है, वह है शौचालयों का न होना। पीड़िताओं को अंधेरा होने के बाद भी घर से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि उनके घरों में शौचालय नहीं थे। शौचालयों का अभाव न केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी यह बड़ी चुनौती है। भारत में सफाई की कमी यहां के बच्चों में पाये जाने वाले कुपोषण की गंभीर समस्या का मूल कारण है और इसका पता इसी से लगता है कि देश में बच्चों में कुपोषण की दर अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्रों से भी अधिक है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और गंदा वातावरण यहां बीमारियों को पैदा होने और कुपोषण को बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक हो रहे हैं। सफाई और शौचालयों की कमी के कारण बच्चे टायफायड और डायरिया जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ रहे हैं। ये रोग बच्चों की क्षमताओं का ह्रास करते हैं। यह साबित हो चुका है ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में गंदगी का असर सीधे-सीधे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका प्रमाण अलग-अलग राज्यों में सफाई और शौचालय की व्यवस्था तथा कुपोषण के आंकड़ों से भी मिलता है। केरल, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम जहां के अस्सी फीसद से ज्यादा ग्रामीण घरों में शौचालय की सुविधा मौजूद है, वहां बच्चों में कुपोषण की दर बेहद कम है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में जहां की अधिसंख्य आबादी शौचालय से वंचित हैं, वहां बच्चों में कुपोषण की दर सर्वाधिक है।

भारत में विश्व में सबसे ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं (डब्ल्यूएचओ-यूनिसेफ)। जिन लोगों के पास अपनी जमीन है, उनके पास शौच के लिए खुली जगह भी है लेकिन जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें ऐसी जगह की तलाश में कई बार मीलों दूर जाना पड़ता है जो शौच के लिए सुरक्षित हो। ऐसा करना उनके समय, प्रयासों और क्षमता का अपव्यय है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बीमार, विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए तो अपनी प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करना बहुत ही खतरनाक और अमर्यादित काम बन जाता है। इसके साथ ही जलस्रोतों और खेतों में शौच करना सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। स्कूलों में शौचालय के न होने का खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है और उनके स्कूल न जाने का यह बड़ा कारण बन जाता है। ब्रिटिश व्यंग्यकार जॉन ओलीवर ने अपने व्यंग्य शो में भारतीय चुनावों पर कटाक्ष करते हुए कहा था "नरेंद्र मोदी ने हर घर में शौचालय का नारा देकर लोगों को अपनी ओर कर लिया है। शौचालय समर्थक के रूप में सामने आना बहादुरी भरा कदम है।" भले ही जॉन ने नरेंद्र मोदी की बातों को मजाक में उड़ा दिया हो लेकिन 2014 के चुनाव अभियानों में सफाई को फोकस करना स्वागतयोग्य है। एक सार्वजनिक रैली में मोदी ने कहा था 'पहले शौचालय, फिर देवालय'। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी पर अपनी पंक्ति को चुराने का आरोप लगाया था। श्रेय चाहे किसी को भी जाय लेकिन बड़े राजनेताओं द्वारा शौचालयों को गंभीरता से लिया जाना अपने आप में उल्लेखनीय है। याद दिला दें कि वर्ष 2011 में जब केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल किया गया था तब कांग्रेस के गुरदास कामत ने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का भार ग्रहण करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह काम उन्हें छोटा लगा था।

स्वच्छता का महत्व तो देश की दो बड़ी पार्टियों के चुनावी घोषणापत्रों को देखने से ही पता लग जाता है। वर्ष 2009 में जहां बड़े राजनीतिक दलों ने अपने घोषणापत्रों से स्वच्छता को गायब कर

## हमारी बात

**मुख्य संपादक**

**नीना श्रीवास्तव**

**संपादन**

**दीपिका**

**शोध**

**नीना श्रीवास्तव**
**दीपिका**

**प्रबंधन/व्यवस्था**

**राहुल कुमार**

**प्रकाशन**

**इक्विटी फाउंडेशन**

**सहयोग**

**जीवक हार्ट हॉस्पीटल, पटना**
**केनरा बैंक**
**भूषण इंडस्ट्रीज, पटना**

**संपर्क**

**123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी**
**पटना, 13**
**फोन : 0612-2270171**
**ई-मेल**
**magazinemanjari@gmail.com**

उसे विशिष्ट बना दिया था वहीं वर्ष 2014 के आम चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही खुले में शौच मुक्त भारत बनाने का वादा किया है। साफ-सफाई को मान्यता देने की ओर यह बड़ा कदम है। साथ ही देश के विकास को बाधित करने में गंदगी का कितना स्थान रहा है, इस ओर भी लोगों का ध्यान जाने लगा है। भारत की जनगणना के मुताबिक देश में आधे से ज्यादा घरों के लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते और खुले में शौच की प्रवृत्ति बच्चों में व्याप्त कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में एक शौचालय के निर्माण पर होने वाले खर्च का सिर्फ पांच रुपये ही लौट कर आता है।

हाल के शोधों ने साबित किया है खुले में शौच की प्रवृत्ति का गहरा संबंध खराब स्वास्थ्य से होता है। अमेरिकन इकोनोमिक एसोसिएशन के हाल में हुए कान्क्लेव का पूरा एक सत्र जिसे 'टॉयलेट पेपर' नाम दिया गया था, बच्चों के स्वास्थ्य पर सफाई के असर के नाम कर दिया गया था। इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि खुले में शौच की आदत को छोड़ने से पूरी दुनिया में बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। शोधों ने यह भी बताया है कि कई मामलों में शौचालयों का असर बच्चों की लंबाई पर भी पड़ता है। हालांकि बच्चों की लंबाई पर जीन का असर पड़ता है या सफाई या मां के स्वास्थ्य का, इस बारे में पुरा पाषाण विवाद अब भी जारी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली में 2013 में लिखा था कि भारतीय बच्चे आनुवंशिक कारणों से अफ्रीका के सब सहारा के बच्चों से कम लंबे होते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस कार्यप्रणाली को दोषी ठहराया जाना चाहिए जिसने इस बात को प्रसारित किया कि भारतीय बच्चों में कुपोषण की दर अफ्रीकी बच्चों से ज्यादा होती है और यह उनकी लंबाई को बाधित करती है। दूसरी ओर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री डीन स्पीयर्स ने अरविंद के दावे को खारिज करते हुए 'मिंट' में लिखा कि अलग-अलग देशों के बच्चों के कद में अंतर का बड़ा कारण साफ-सफाई है। स्पीयर्स और उनके दो सहयोगियों अरविंद घोष और आशीष गुप्ता ने अपने शोध से इस दावे को साबित किया। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के बच्चे अपने सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के बच्चों से ज्यादा लंबे होते हैं क्योंकि बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल की तुलना में कम लोग खुले में शौच करते हैं। इसी तरह कंबोडिया में पिछले दस सालों में खुले में शौच के मामलों में तेजी से कमी आई है और अकेले इस वजह से वहां के बच्चों की लंबाई में इजाफा देखा गया है। घोष और ओलीवर के साथ भारत के सौ गांवों में किये अपने एक और अध्ययन में स्पीयर्स ने पाया कि खुले में शौच के मामलों में दस फीसद की भी वृद्धि कुपोषण और गंभीर कुपोषण के मामलों में .7 अंक की बढ़ोतरी कर देता है। स्वच्छता को पूरी तरह अपनाना आसान काम नहीं हैं क्योंकि भारत में लोगों की आदतें उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। हालांकि सब्सिडी लोगों को शौचालय निर्माण की तरफ आकर्षित करती हैं लेकिन कई बार वह इतनी कम होती है कि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

अपने और अपने परिवार के लिए जिंदगी जीने की मानक सुविधाओं को हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार है। इसमें समुचित भोजन, वस्त्र, मकान, पानी और शौचालय व स्वच्छता शामिल है। 1996 में यूनाइटेड नेशन के कांफ्रेंस में 171 देशों ने भी मानव बस्तियों के एजेंडे को अपनाया था जिसमें कहा गया था कि साफ पानी और शौचालय व स्वच्छता केवल रोगों से बचाव और हाइजीन के लिए जरूरी नहीं है बल्कि यह इंसान के सम्मान के लिए भी जरूरी है। सेहत और सम्मान के साथ जीवन जीना विश्व के हर इंसान का अधिकार है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वच्छता हर व्यक्ति का अधिकार है।

नीना श्रीवास्तव

# अनुक्रमणिका


## हमारी बात

- संपादकीय

## पहल

- जब कोई न दे साथ एकला चलो रे

## अतीत

- संपन्न रहा है शौचालयों का इतिहास

## सोचो-समझो

- जरूरत नहीं बदलेगी, आदत बदलनी होगी
- साफ हों हाथ तो बन जाये बात

## चिंतनीय

- शौचालय : सवाल अस्मिता का

## ग्लोबल जिम्मेदारी

- चिंता में संयुक्त राष्ट्र भी
- विशेषज्ञों को है दायित्व का अहसास

## दृष्टिकोण

- हरेक के लिए एक शौचालय
- एक छिपी हुई समस्या है शौचालय
- खुले में शौच की प्रवृत्ति एक सांस्कृतिक विकृति

## भारी पड़ती गंदगी

- गरीब करते हैं गंदगी का भुगतान
- गंदगी + खुले में शौच = कुपोषण व छोटा कद

## विचार मंच

- बदलते समय की मांग है राइट टू पी
  प्रो. विभूति पटेल

## आंखों देखी

- हर हाथ में मोबाइल का फायदा क्या ?
  डा. मीरा मिश्रा

## अध्ययन

- अच्छी सेहत की गारंटी नहीं है स्वच्छता अभियान

## रियल हीरो

- संकोच की चुप्पी तोड़ने की हिम्मत


स्रोत : वाटरएड, बीबीसी.कॉम, फ्लूट्रैकर्स.कॉम, द हिंदू, इंडिया टुडे, इंडियाटुगेदर.कॉम, हिन्दुस्तान टाइम्स, द संडे इंडियन, गुगल, गेटीइमेज.कॉम, हिस्ट्रीबिट्स.कॉम, इक्विटी फाउंडेशन, आउटलुक.कॉम, रायटर, विकीपीडिया

## जब कोई न दे साथ

# एकला चलो रे

27 मार्च, 1928 को सफाई कर्मचारियों के साथ एक बैठक करते हुए महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से पूछा था कि सफाई कर्मचारियों को कितने पैसे मिलते हैं। तब सरदार ने उन्हें बताया कि नगर निगम महिला कर्मचारियों को 12 रुपये, पुरुषों को 14 रुपये और सुपरवाइजरों को 16 रुपये भुगतान करता है। गांधी जी ने सफाई कर्मचारियों से उनके शराब पीने और जुआ खेलने की आदत के बारे में भी पूछा और कहा कि आप लोग सफाई की खेती करें जिससे कि आपको अछूत नहीं माना जाय। बापू ने कहा कि सफाई कर्मियों को तब तक उनका साथ नहीं मिल पाएगा जब तक कि वे अपनी खराब आदतों को छोड़ नहीं देते। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी जुआ खेलने और शराब पीने की आदत नहीं छोड़ देते और पैसे की अहमियत को नहीं समझते, तब तक नगर निगम आपकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाएगा।

राष्ट्रपिता बापू वो शख्स थे जिन्होंने सफाई के महत्व को न केवल समझा था बल्कि लोगों को समझाने के मिशन में भी लगे रहे थे। उन्होंने कहा था कि सफाई करना पूजा करने के समान है। बापू के जीवन के जो किस्से पढ़े या सुनाये जाते हैं उनमें ज्यादातर सफाई को लेकर होते थे। उन्होंने साफ कहा था कि स्वच्छता का महत्व आजादी से भी ज्यादा है। वर्ष 1925 में गांधी जी के सहयोगी डा. हरिप्रसाद देसाई ने पहली सफाई स्पर्द्धा का आयोजन किया था जिसके तहत 222 दिन तक चलने वाली सफाई प्रतियोगिता में शामिल होने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था।

आजादी मिलने के करीब 68 साल बाद सफाई और शौचालय के मामले में भारत की जो स्थिति है वो बेहद शर्मनाक है। यकीन नहीं होता कि जिस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे शख्स हों उस देश की 626 मिलियन जनता खुले में शौच करती है। दुनिया के तमाम पिछड़े देशों को भी पीछे छोड़ते हुए हमारा देश इस मामले में सबसे आगे है। यहां तक कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला चीन भी इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पर है और यहां की केवल 14 मिलियन जनता खुले में शौच करती है। राष्ट्रपिता गांधी ने इस कुरीति के नुकसान को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने शौचालय और साफ-सफाई को बहुत हद तक 'अछूत' से जोड़कर देखा था। तब से लेकर आज तक हमारा देश दलित-ब्राह्मण और पिछड़े-अगड़ों की सामाजिक-राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर नहीं उठ सका है। गांधी जी ने लोगों के मन से इस दुर्भावना की सफाई करने को अपना मिशन बनाया था।

**गौर कीजिए**

**हफ्ते में केवल दो घंटे और साल में कम से कम एक सौ घंटे सफाई के लिए जरूर दें : नरेंद्र मोदी**

वे कहते थे कि  किसी व्यक्ति के मन में किसी अन्य व्यक्ति से ऊपर होने की भावना भगवान और इंसान दोनों के प्रति अपराध है। एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति अगड़ा और पिछड़ा होने की इस नीयत को बदलने के लिये ही गांधी जी अपने आश्रमों में अपना शौचालय खुद साफ करते थे। उन्हें देखकर आश्रम में रहने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही करने लगे थे।

गांधी जी अक्सर कहा करते थे "शायद मैं फिर से जन्म नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो मैं चाहूंगा कि मैं मैला ढोने वाले के घर में जन्म लूं ताकि मैं उन लोगों को अमानवीय होने, अस्वस्थ होने और मैला ढोने के घृणित कार्य से छुटकारा दिला सकूं।" गांधी जी के तमाम प्रयासों के बाद सिंधी समुदाय के लोगों में जब साफ-सफाई के प्रति जागरूकता नहीं आ पाई थी तो उन्होंने मीरा बेन से विनती की थी कि वे जाकर सिंधियों के बीच रहें और अपने कामों से उदाहरण पेश करें। उनका मानना था कि एक अकेला इंसान भी अपने कामों से लोगों के नजरिये को बदल सकता है। लोग तब तक नहीं सीखते जब तक किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखते। गांधी जी की यह सोच कर्म के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए जरूरी है। स्वच्छता के प्रति महात्मा गांधी की दीवानगी का एक और उदाहरण देखने को मिला जब 1927 में उन्हें मायावरम नगर निगम में अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में गांधी को समाज सुधारक और मानवतावादी के रूप में पेश किया गया था। जब गांधी ने अपना संबोधन शुरू किया तो कहा कि आज के कार्यक्रम में वे स्वच्छता और शौचालय के संबंध में बोलना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप मुझसे समाज सुधार की बात सुनना चाहते हैं लेकिन मेरे विचार से स्वच्छता एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर मानवतावादी और समाज सुधारक को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जहां मेरे रहने की व्यवस्था की है, वहां तीन-चार मिनट तक टहलने के दौरान मैंने एक लकड़ी का पुल बना देखा जो बहुत खूबसूरत था लेकिन मैं जैसे ही उस पुल पर चढ़ा वहां से तेज बदबू  आई। मैंने देखा कि पुल के नीचे तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया था। उसी समय वहां एक महिला आई और उसने अपने बर्तन में तालाब का गंदा पानी भरा। बापू ने कहा कि किसी भी नगर निगम के लिए पहली शर्त यही होती है कि वहां पूरी तरह साफ-सफाई हो और शुद्ध पानी की व्यवस्था रहे। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको पैसे की नहीं बल्कि इच्छाशक्ति और अपने ड्यूटी के प्रति समर्पण की जरूरत है। इसी तरह 1938 में कांग्रेस के एक शिविर में सफाई का काम कर रहे कार्यकर्ताओं को महात्मा ने कहा था " यह न समझें कि आपका काम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के काम से किसी भी तरह से कम महत्व का है। बिल्कुल भी नहीं। वे सेवा कर रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं। बल्कि मैं तो आपके काम को ज्यादा तरजीह देता हूं। मैं स्वयं एक अनुभवी भंगी (मैला ढोने वाला) हूं। आप अपना काम ईमानदारी और समझदारी से करें। आप जानते हैं कि जो काम आप करते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। भंगियों को सबसे हेय दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि लोग उनके द्वारा किये जाने वाले काम को घृणित समझते हैं लेकिन वे उस काम की महत्ता को दरकिनार कर देते हैं।"  गांधी जी ने अपनी बातों को ज्यादा तार्किक बताते हुए कहा था कि हम भूल जाते हैं कि हमारी मां ने यह काम

## बापू ने कहा था

**पश्चिम के देशों से हमें एक चीज सीखनी चाहिए-नागरिकों में सफाई का विज्ञान। वहां के देशों में सामूहिक स्वच्छता का जो विज्ञान अपनाया है वह काबिल-ए-तारीफ है और हमें भी सफाई के उनके रास्ते पर चलना चाहिए।**

**-यंग इंडिया, 1924**

**जहां स्वच्छता है, वहीं भगवान हैं। गंदे शरीर और गंदी मानसिकता के साथ मांगे गये आशीर्वाद हमें नहीं मिलते।**

**-यंग इंडिया, 1925**

**टैक्स चुका देने और पैसे दे देने भर से कोई नगर निगम गंदगी से नहीं लड़ सकता। यह तभी संभव है जब अमीर और गरीब मिलकर और स्वेच्छा से गंदगी के खिलाफ मिलकर लड़ें।**

**-यंग इंडिया, 1925**

बहुत पहले ही किया था जब हम बच्चे थे। अगर हमारी मां का वह काम घृणित था तो भंगी भी घृणित हैं लेकिन अगर मां का काम पवित्र था तो भंगियों का काम भी पवित्र माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारी मांओं ने हमारे मल को इसलिए साफ किया क्योंकि हम उनके बच्चे थे और उनकी भावनाएं और उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई थीं लेकिन अगर भंगियों को देखें तो वे बिना किसी उम्मीद और भावना के लोगों के मल को ढोते हैं। इस हिसाब से भंगियों के काम को माताओं के काम से भी ज्यादा सम्मान देने की जरूरत है।

मैला ढोने वालों के प्रति गांधी के प्रेम को इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब भी वे दिल्ली या बंबई जाते थे तो हरिजनों के कॉलोनी में रुकते थे। उस दौरान चाहे कोई राजनीतिक नेता हो या विदेशी मीडिया प्रतिनिधि, किसी भी मसले पर बात करने के लिए उन्हें मैला ढोने वाले लोगों की कॉलोनी में जाकर ही गांधी से बात करनी होती थी। ये उदाहरण स्वच्छता और सफाई कर्मियों के प्रति गांधी जी के समर्पण को जाहिर करने के लिए काफी हैं। जब तक ऐसा ही समर्पण और कार्यशीलता तमाम लोगों और संगठनों में पैदा नहीं होगी तब तक संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को पाना मुश्किल होगा। यह जानते हुए भी गांधी का अनुसरण कर पाना मुश्किल है, करोड़ों लोग उनके सिद्धांतों के मुरीद हैं। उन्होंने बार-बार कहा कि दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमारा दुश्मन हमारे भीतर है। कह सकते हैं कि अगर हमें एमडीजी के लक्ष्य को पाना है तो हमें गांधी के वचनों को अपनाना होगा। लगातार दो बार वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष रह चुके जेम्स वुल्फेनशन ने गांधी की ही तरह आर्थिक सम्पन्नता को लोगों की नैतिकता से जोड़ा था। करीब 60 से 70 देशों का दौरा करने और खासकर वहां के गरीबों से मिलने के बाद जेम्स ने कहा था कि वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य आर्थिक प्रगति को उस देश की आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति के साथ मिलाकर पाना है। इसके लिए जेम्स ने दुनिया भर के धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं का आह्वान किया था कि वे गरीबी और विकास के मुद्दों पर एक साथ आएं और लोगों को प्रेरित करें। गांधी जी भी लोगों को नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए कहते थे ताकि वे दूसरों के साथ-साथ अपने जीवन को भी सुंदर बना सकें। वो गांधी ही थे जो गरीबों और वंचितों की आत्मा तक पहुंच पाये और हतोत्साहित तथा टूट चुके लोगों को अपनी कमर सीधी का सिर उठा कर चलने का हौसला दिया।

## नवजीवन में गांधी जी ने लिखा था

**2 नवम्बर, 1919 को अपने लेख में गांधी ने अच्छे स्वास्थ्य का अच्छी आदतों से संबंध के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने लिखा '' किसी को भी सड़क या गलियों में न तो थूकना चाहिए और न ही नाक साफ करना चाहिए। थूक में पाए जाने वाले कीटाणु कभी-कभी इतने नुकसानदेह होते हैं कि इससे लोगों में तपेदिक जैसी बीमारी भी हो सकती है। पान और खैनी खाकर सड़कों पर थूकने वाले लोगों को दूसरों का बिल्कुल ध्यान नहीं होता।''**

**''गांवों में या घर के आस-पास गड्ढों में पानी जमा होने से बचाना चाहिए। बहते हुए पानी में मच्छर अंडे नहीं देते हैं। अगर मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा। एक समय में दिल्ली के आस-पास पानी जमा रहता था जिसके कारण वहां मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप बना रहता था। लेकिन पानी निकाले जाने के बाद मलेरिया के प्रमाण कम मिल रहे हैं।''**

**इसी तरह 24 मई 1925 को उन्होंने लिखा '' पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान मैंने 35 साल पहले यह सीखा था कि अपने शौचालय को ड्राइंगरूम की तरह साफ रखना चाहिए। हमारे देश में ज्यादातर बीमारियां शौच के समय की गंदगी और लोगों की बुरी आदतों की वजह से होती है। जहां-तहां शौच और मूत्र त्याग करने से कई बीमारियों को मौका मिल जाता है। शौच की सही आदतों को अपनाना सबके लिए जरूरी है। मुझमें यह आदत इस तरह समा चुकी है कि अब मैं इसे छोड़ना भी चाहूं तो नहीं छोड़ सकता। मैं कभी इसे छोड़ना नहीं चाहूंगा।''**

# संपन्न रहा है शौचालयों का इतिहास

**दुनिया की सबसे बड़ी और दिलचस्प खोज हैं आधुनिक शौचालय। ईसा पूर्व 2800 से ज्ञात शौचालयों का इतिहास बहुत रोचक है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वज जिन्हें आज की पीढ़ी हाईटेक नहीं मानती, हमसे कहीं अधिक सभ्य और आधुनिक थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं ने भी स्वच्छता के महत्व को समझा था और शौचालय की व्यवस्था को अपनाया था।**

## 2800 ईसा पूर्व बनी थी पहली फ्लशिंग ट्यालेट

संभवतः विश्व की पहली फ्लशिंग ट्यालेट 2800 ईसा पूर्व मिस्र के मिनोओ क्रेटे में बनाई गई थी। अब तक की खोजों से पता चलता है कि मिनोआ के लोग शौच के समय जिस चीज का इस्तेमाल करते थे वह बिल्कुल हमारी आधुनिक फ्लश सिस्टम से मेल खाती थी। तब के लोग बहते पानी के ऊपर एक शीट बनाकर शौच के लिए बैठते थे जिसमें शौच के बाद पानी के बहाव के लिए एक हैंडल जैसी मशीन लगी होती थी। कालांतर में जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और लोगों में खोज और आविष्कार करने की ललक बढ़ती गई, शौचालय के नये और ज्यादा सुविधाजनक संस्करण सामने आते गये। इसी के तहत कई सभ्यताओं के दौरान सार्वजनिक शौचालयों के अस्तित्व सामने आये जहां लोग समूह में स्नान करते थे या कपड़े साफ करते थे।

## जॉन हेरिंगटन ने बनाई घरेलू फ्लश शौचालय

शौचालयों के निर्माण में सबसे बड़ी क्रांति 1500 ईसवी के अंत में आई जब ब्रिटेन में जॉन हेरिंगटन ने दुनिया की पहली घरेलू फ्लशिंग शौचालय का निर्माण किया। अब तक लोगों में गंदगी और मानव मल से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैल चुकी थी और दुनिया भर में कॉलरा और

प्राचीन यूनान में बच्चों को शौच की ट्रेनिंग देने के लिए बनाये गये उपकरण।

डायरिया जैसे रोगों के लिए इन्हें मुख्य कारण माना जाने लगा था। ऐसे में जॉन के इस आविष्कार ने सफाई के नये युग की शुरुआत कर दी। जॉन हैरिंगटन रानी एलिजाबेथ वन के पोते थे और उन्होंने इस शौचालय का निर्माण अपनी बीमार दादी की सुविधा के लिए तैयार किया था। कालांतर में उन्नीसवीं, बीसवीं और इक्सवीं शताब्दी में शौचालय निर्माण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय और जरूरी परिवर्तन आये। पानी की सही व्यवस्था और मल की निकासी के लिए कई नये-नये तरीके अपनाये गये।

## थॉमस क्रैपर ने ला दी थी क्रांति

उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड के मशहूर प्लंबर थॉमस क्रैपर ने शौचालय के क्षेत्र में कई प्रयोग किये। फ्लशिंग शौचालय, बाथटब, वॉश बेसिन और आधुनिक पाइपिंग इन्हीं की देन रही। क्रैपर की कंपनी ने आधुनिक शौचालय को लोकप्रिय बना दिया जिसके कारण बाद में फ्लशिंग शौचालय को उनकी कंपनी के नाम से ही जाना जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज ने पहली बार इंग्लैंड में क्रैपर शौचालयों को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब तक वे घर के बाहर बनने वाले साधारण लैटरिनों का इस्तेमाल किया करते थे लेकिन इंग्लैंड में क्रैपर के घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले फ्लशिंग शौचालयों को देखना उनके लिए नया अनुभव था। जब वे लौट कर अपने देश आये तो उन्होंने इसे प्रचारित करना शुरू किया जिसके कारण जल्दी ही क्रैपर शौचालय अमेरिका में भी लोकप्रिय हो गये।

## भारत में शौचालयों का इतिहास

विश्व के कई देशों में आधुनिक शौचालयों के प्रचार-प्रसार के बाद भी कई एशियाई देशों जिनमें भारत भी शामिल है, शौचालय की सुविधा सबको प्राप्त नहीं है। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जो खुले में शौच करते हैं। इसके पीछे शौचालयों की कमी तो एक वजह है ही लेकिन उससे भी बड़ी वजह है लोगों की मानसिकता। दुख की बात ये है कि इसके पीछे लोग भारतीय पुरातन ग्रंथों को वजह मानते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि भारत में पुरातन काल से खुले में शौच के लिए प्रेरित किया जाता रहा है लेकिन यह गलत है। न तो भारत की किसी संस्कृति में खुले में शौच का समर्थन किया जाता है और न ही ऐसा करने के लिए कहा गया है बल्कि अर्थ को ठीक ढंग से समझा जाय तो पायेंगे कि इनमें शौच की सही प्रक्रिया को ही समझाया गया है।

## मनुस्मृति और कामसूत्र

में बताया गया है कि मानव मल और अन्य क्रियाओं के बीच निश्चित दूरी रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में शौच करने के स्थान और खाने, सोने या रहने के स्थान के बीच दूरी होनी चाहिए, इनमें कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। साथ ही इनमें यह भी बताया गया कि मानव मल या अवशेष को किसी भी तरह के पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। खेती के दौरान भी मानव मल का संपर्क नहीं होना चाहिए। यानी इन ग्रंथों ने साफ-साफ कहा है कि खेतों में, जहां अनाज की पैदावार होती है और नदियां जहां से पीने के पानी की आपूर्ति होती है, वहां मल त्याग नहीं करना चाहिए। इनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि शौच करने के लिए नदी या तालाब के किनारे या खेतों-मैदानों का इस्तेमाल करना चाहिए बल्कि इनमें रोगों से बचाव के लिए अपनाये जाने वाले यूरोपीय फार्मूले की बहुत पहले ही व्याख्या कर दी गई थी। पुराने समय में जाएं तो हम पाएंगे कि उस समय जनसंख्या कम थी। लोग शौच के लिए घर से दूर जाते थे उन स्थानों पर जो नदियों या कुओं से अलग हों। वे शौच के लिए गड्ढे करते थे और शौच के बाद उन्हें मिट्टी से ढंक देते थे। इसके बाद हाथ धोने के लिए वे प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते थे। इस तरह वे सफाई के नियमों का पालन कर खुद को और समाज को कई तरह के रोगों से बचा लेते थे। देश में ब्रिटिश हुकूमत के पहले तक तालाबों और पानी के अन्य स्रोतों के दोहन और इस्तेमाल की सही प्रक्रिया काम कर रही थी। राजा पानी के स्रोतों के रख-रखाव पर उचित राशि खर्च करते थे तो आम लोग मजदूरी कर उसके बचाव के लिए उपाय करते थे। तब तक लोग व्यक्तिगत रुचि लेकर पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते थे। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब देश की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। खुली जगहों की कमी हो गई और मोहल्ले घने होते गये। लोग अपने घर से दूर जाकर मल त्याग करते थे लेकिन वह स्थान किसी और के घर के नजदीक होता था। नतीजतन गंदगी फैलने लगी और आस-पास के लोग उसकी चपेट में आने लगे। मल को मिट्टी से ढंकने के तरीके को सही तरीके से प्रचारित नहीं किये जाने के कारण लोगों ने इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया। शौच के पूर्वजों द्वारा बताये गये तरीके धुंधले पड़ते

चले गये और ब्रिटिशों के चकाचौंध में नये तरीके ठीक से समझने के मौके नहीं मिले। तिस पर से गरीबी की मार ने हाइजीन और सफाई की तरफ से लोगों का ध्यान पूरी तरह हटा दिया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान पानी के रख-रखाव के लिए अपनाये गये पुराने तरीकों को फिजूलखर्ची बताकर छोड़ दिया गया जिससे पानी की टंकिया और अन्य मशीनरी जर्जर होती चली गई। संक्रमण के उस दौर में साफ-सफाई सबसे कम जरूरी चीजों में

**गौर कीजिए**

**मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश के ग्यारह लाख स्कूलों में से दस फीसद स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है।**

शामिल होती गई। पूर्वजों ने भारतीयों को सफाई के जो तरीके समझाये थे वे कहीं ज्यादा सही और प्रदूषण रहित थे। मल को साफ पानी के संपर्क में नहीं आने देने के सिद्धांत को यदि वैज्ञानिक ढंग से लोगों को समझाया जाता तो आज भारत इको फ्रेंडली शौचालयों वाले देश के तौर पर जाना जाता और उसे 700 डॉलर प्रति टन के हिसाब से उर्वरकों का आयात नहीं करना पड़ता। यूरोप में आविष्कृत फ्लश शौचालय भी पर्यावरण के हिसाब से सही नहीं हैं क्योंकि इसमें पानी को मल के साथ मिलाया जाता है जो अंततः नदी या तालाब में जाकर मिल जाता है। यह प्रदूषण को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं जबकि भारतीय पुराणों में प्रदूषणरहित मल विसर्जन के उपायों के बारे में बताया गया है।

## सिंधु घाटी सभ्यता

पांच हजार साल पहले सिंधु नदी के किनारे फलन-फूलने वाली सिंधु घाटी सभ्यता में दुनिया की सबसे विकसित जल निकासी और आपूर्ति की प्रणाली थी। यह सभ्यता देश के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र की ओर भी फैली हुई थी। इस सभ्यता के बेहद साफ और शौचालययुक्त होने का प्रमाण यहां होने वाली खुदाइयों से भी मिलता रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों से यह पता चला है कि पूरे क्षेत्र में नालियां ढंकी होती थीं जबकि गलियों में गंदगी नहीं जमने का पूरा इंतजाम किया जाता था। इसी तरह की प्रणाली का पता गुजरात के धौलावीरा में भी देखा गया था। भारत नदियों और तालाबों का देश है और यहां बारिश भी बहुतायत में होती है। देश में सबसे पुरानी जल कृषि प्रणाली पुणे से 130 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट के किनारे नानेघाट है। यहां के पथरीले रास्तों पर व्यापारियों के लिए जो रूट बनाया गया था उसमें पहाड़ों को काट कर पानी की टंकियां बनाई गई थीं। उस क्षेत्र में स्थित हर किले में अपनी जल संचय प्रणाली बनाई गई थी जो ज्यादातर पत्थरों को काट कर बनाये गये थे। इसके अलावे तालाब, टंकियां और कुएं भी जगह-जगह बनाये गये थे जिन्हें खोज के दौरान देखा जा सकता था। इसी तरह पुराने जमाने में राजस्थान में भी पानी के संचय के लिए प्रणाली का विकास हो चुका था। यहां लगभग हर घर की छत पर जल संचय के लिए उपक्रम बनाये जाते थे जो पाइप के सहारे भूमिगत टंकियों से भी जुड़े होते थे। आज भी राज्य के पुराने किलों और महलों में उस प्रणाली के प्रमाण देखे जा सकते हैं।

## ब्रिटिश शासनकाल में स्वच्छता का महत्व

अधीन भारत में 1859 में रॉयल कमीशन के गठन के बाद स्वच्छता की दिशा में पहल की गई। ब्रिटिश फौज में होने वाली बीमारियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने यह कमीशन गठित की थी जिसने सन् 1863 में अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में तैनात ब्रिटिश फौज में प्रति एक हजार पर 69 सैनिक किसी न किसी बीमारी का शिकार होकर मारे जाते हैं। रिपोर्ट में हर प्रेसीडेंसी में स्वास्थ्य कमीशन गठित करने की सिफारिश की गई और साथ ही साथ नागरिक समाजों में भी साफ-सफाई के लिए अभियान चलाने की जरूरत बताई गई। इसके बाद 1864 ईसवी में फौज और नागरिक समाज, दोनों के लिए स्वच्छता बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 1870 में स्वच्छता विभाग को टीकाकरण विभाग से संलग्न कर दिया गया। 1870 से लेकर 1879 तक हर प्रोविंस में एक स्वच्छता विभाग का गठन किया गया और 1880 में स्वच्छता अभियंताओं की नियुक्ति की गई। स्वच्छता कमिश्नरों को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिये गये थे और वे सरकार के सलाहकार के तौर पर काम करते थे। उनका काम जिलों में साफ-सफाई का निरीक्षण करना, उनकी देखरेख का जिम्मा लेना और आंकड़ों के साथ पूरी स्थिति से सरकार को अवगत कराना था। वर्ष 1885 में स्थानीय निकायों का अस्तित्व सामने आया और हर जिले में स्थानीय निकायों का गठन किया गया। अब साफ-सफाई की पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में थी। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने डिप्टी सैनिटरी कमिश्नरों और स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति की और अब स्थानीय निकायों को स्वच्छता के लिए भी फंड दिया जाने लगा।

## फ्लोरेंस नाइटिंगेल का योगदान

अधीन भारत के इतिहास में लोगों की साफ-सफाई की ओर ध्यान दिलाने में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। 1857 के गदर के दौरान बीमारियों से मरने वाले ब्रिटिश सैनिकों की हालत देखकर फ्लोरेंस ने यह महसूस किया कि फौज में साफ-सफाई का ध्यान अगर रखा जाय तो मृत्यु दर कम हो सकती है। जल्दी ही उन्होंने आम भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छता की जरूरत को महसूस किया और उसके बाद करीब चालीस साल तक इस क्षेत्र में काम करती रहीं। उन्होंने इस बात को गहराई से समझा कि भारतीयों में पाई जाने वाली बीमारियों की जड़ में उनके आस-पास सफाई का न होना और उनकी दैनिक क्रियाकलापों में भी स्वच्छता का ध्यान न रखना शामिल है। उन्होंने 1859 में गठित रॉयल कमीशन का ध्यान इस ओर दिलाया। 1874 में उन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व को बताया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित स्वच्छता कमीशन को और ज्यादा कार्यशील और प्रभावपूर्ण बनाने में फ्लोरेंस के कार्य बेहद मददगार रहे। उन्होंने सरकार को इस बात का अहसास दिलाया कि बिना भारतीयों की मदद के हम किसी भी कानून को कामयाबी नहीं दिला सकते।

**गौर कीजिए**

**स्वच्छ भारत अभियान से सेरामिक टाइल्स बनाने के व्यवसाय में पंद्रह फीसद तक का इजाफा होने की उम्मीद है।**

# जरूरत नहीं बदलेगी, आदत बदलनी होगी

**जितनी जिम्मेवार सरकारी उदासीनता है उतनी ही आम भारतीयों की मानसिकता भी। देशवासियों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी भी लोगों की इस मानसिकता से भलीभांति परिचित थे। गांवों में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने लोगों को शौचालय का महत्व बताने के लिए तैनात किया था। वे कार्यकर्ता लोगों का मैला तक साफ करने के लिए तैयार रहते थे। उन दिनों गांव वालों की मानसिकता के बारे में गांधी जी के सचिव माधव देसाई ने लिखा है " इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दिनों के बाद गांव वाले इन कार्यकर्ताओं को उनका मैला ढोने वाला मान लेंगे।"**

'अग्नि मिसाइलों के प्रक्षेपण पर करोड़ों खर्च कर देने का कोई मतलब नहीं है, अगर हमारे देश में पर्याप्त शौचालय नहीं हैं।" पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने संप्रग के शासनकाल में ही देश के आला हुक्मरानों सहित आम लोगों को भी शौचालय की जरूरत और खुले में शौच के नुकसान के बारे में आगाह करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बार ये स्वीकार किया कि वे अपना ज्यादातर समय देश में शौचालयों की व्यवस्था के संबंध में सोचने पर व्यतीत करते हैं। उनके मुताबिक अगर लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं तो देश में बड़ी-बड़ी मिसाइलों के प्रक्षेपण का कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ एक लड़ाकू विमान को बनाने में आने वाली लागत हजारों देशवासियों को खुले में शौच जाने से आजाद कर सकती है।

खुले में शौच जाने की समस्या और इसके दूरगामी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों पर जयराम रमेश की चिंता को आगे लेकर बढ़े हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदूवादी छवि के होने के बाद भी पीएम मोदी ने कई सार्वजनिक जगहों पर कहा है कि देश में 'पहले शौचालय, फिर देवालय।' अपनी चिंता के निवारण के लिए मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को आधार बनाते हुए स्वच्छता अभियान को नया रूप दिया और आम लोगों के साथ-साथ जानी-मानी हस्तियों को इससे जोड़ा है। अभियान जारी है और कमोबेश इसके नतीजे सामने आने लगे हैं।

जयराम रमेश और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने शौचालय न होने की वजह से खुले में शौच की लोगों की प्रवृत्ति के भयानक दुष्परिणामों को भांप लिया है। वे यह जानते हैं कि देश में 64 फीसद लोग खुले में शौच करते हैं जो एक रिकार्ड है और विश्व के सामने शर्मनाक सच है। पूरी दुनिया में जितने लोग खुले में शौच करते हैं उनमें से 60 फीसद लोग भारत के हैं। वे यह भी जानते हैं कि शौचालय का इस्तेमाल न कर झाड़ियों के बीच या अन्य खुली जगहों पर शौच जाने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपना घर बना लेती हैं और यही वजह है कि देश में जीडीपी का 6.4 फीसद स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। फिर भी ये दुखद है कि हमारे देश में जीडीपी का महज 0.2 फीसद शौचालय और स्वच्छता पर खर्च किया जाता है। पिछले दस साल से चलाए जा रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत यह दावा किया गया है कि देश में 8.71 करोड़ शौचालय बनाकर सौंपे गये हैं जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारतीय घरों में केवल 5.16 करोड़ शौचालय ही मौजूद हैं। इसके अलावा आंकड़ों के मुताबिक गांवों में स्वच्छता अभियान चलाने पर पिछले पांच साल में 45 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और 2017 तक 1.08 लाख करोड़ खर्च किये जाने की योजना है।

देश में शौचालयों की सोचनीय स्थिति के लिए जितनी जिम्मेवार सरकारी उदासीनता है उतना ही आम भारतीयों की मानसिकता भी। देशवासियों को साफ-सफाई के लिए प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी भी लोगों की इस मानसिकता से भलीभांति परिचित थे। गांवों में अपने

**गौर कीजिए**

**देश के 11.3 करोड़ घरों में शौचालय मौजूद नहीं है।**

सोचो-समझो

कार्यकर्ताओं को उन्होंने लोगों को शौचालय का महत्व बताने के लिए तैनात किया था। वे कार्यकर्ता लोगों का मैला तक साफ करने के लिए तैयार रहते थे। उन दिनों गांव वालों की मानसिकता के बारे में गांधी जी के अनुयायी, सचिव व डायरी लिखने वाले माधव देसाई ने लिखा है "इसमें कोई शक नहीं कि कुछ दिनों के बाद गांव वाले इन कार्यकर्ताओं को उनका मैला ढोने वाला मान लेंगे।" उन्होंने लिखा कि शौचालय का इस्तेमाल न करना और साफ-सफाई न रखने को लोगों ने अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया है। श्री देसाई और गांधी जी के अनुभव गलत नहीं थे। आजादी मिलने के आधी सदी बीत जाने के बाद भी जबकि देश में बहुत हद तक शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है, ज्यादातर लोग घर के बाहर शौच या पेशाब करते हैं जबकि अपने घर को वे साफ-सुथरा रखना चाहते हैं। ये ठीक है कि राज्य प्रशासन शौचालय की सुविधा का विस्तार कर पाने में नाकामयाब रही है फिर भी लोगों को अपनी मानसिकता को बदलना ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं पढ़े-लिखे और बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी साफ-सफाई को अपने घरों तक ही सीमित रखते हैं। कई जगहों पर देखा गया है कि बड़े-बड़े घरों के कुत्तों को घर से बाहर लाकर या तो दूसरों के दरवाजे पर या सड़क किनारे फ्री करा दिया जाता है। यानी अपना काम बनता, भाड़ में जाये जनता। इतना ही नहीं एक सर्वे में ये भी सामने आया है कि जहां सिख और ईसाइयों के 70 फीसद घरों में शौचालय की सुविधा मौजूद है वहीं हिंदुओं के केवल 45 फीसद घरों में ही यह देखने को मिली। ये आंकड़े साफ-सफाई के प्रति आम भारतीयों की मानसिकता को जाहिर करते हैं।

भारत सरकार ने सबसे पहले 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसे 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जाना जाने लगा। बाद के वर्षों में इसे निर्मल भारत अभियान के तौर पर भी जाना गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि हम एक साल में पचास लाख से ज्यादा शौचालय बनवाने के अभियान में जुड़े हैं और ऐसा हो भी रहा है लेकिन केवल शौचालय बनवा देना ही काफी नहीं साबित हो रहा है। गांवों में शौचालय का इस्तेमाल लोग अपने भंडारगृहों के रूप में करने लगते हैं क्योंकि बहुधा यह कंक्रीट का बना एकमात्र कमरानुमा ढांचा होता है। इसके अलावा केवल 18 फीसद घरों में पानी के पाइप की पहुंच होती है जबकि एक फीसद से भी कम घरों में निकासी की व्यवस्था। ऐसे में शौचालय बनवा देने भर से स्वच्छता अभियान का काम पूरा नहीं हो जाता है। राजधानी दिल्ली में मजदूरी करने वाली एक महिला ने बताया कि सुलभ शौचालय मौजूद होने के बाद भी उसके पति खुले में शौच करना ज्यादा पसंद करते हैं। मंत्रालय के मुताबिक योजना के तहत जारी राशि का 85 फीसद शौचालय बनवाने में और 15 फीसद लोगों को इस बारे में जागरूक करने में खर्च किया जा रहा है फिर भी नतीजे उत्साहवर्द्धक नहीं हैं। अब तक केवल सिक्किम सौ फीसद शौचालय युक्त राज्य बन पया है जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्य अभी भी शर्मनाक स्थिति से ऊपर नहीं उठ पाये हैं। लोगों को शौचालय का महत्व समझाने और उन्हें शौचालय तक पहुंचाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

**गौर कीजिए**

**देश के 11.3 करोड़ घरों में शौचालय निर्माण का कुल खर्च 1.65 लाख करोड़ आएगा।**

# साफ हों हाथ तो बन जाये बात

सफाई अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है और इस कुंजी को पाने के लिए न तो विशेष श्रम की जरूरत होती है और न ही पैसे की। जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति और जानकारी की। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस समय स्वच्छता के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है। इसके लिए विज्ञापनों और गांव-गांव तक शिविर लगाकर लोगों को सफाई के महत्व को समझाया जा रहा है। सफाई की शुरुआत हाथ साफ करने से होती है। हमें यह समझना होगा कि केवल हाथ साफ कर लेने भर से हम खुद को और अपने बच्चों को कई खतरनाक बीमारियों से बचा लेते हैं। फ्लू और सर्दी-जुकाम जैसी संक्रामक बीमारियों को भी साफ हाथों से बाय-बाय कर सकते हैं।

## हाथ साफ नहीं किया तो ?

● अगर हाथ सामने से साफ भी दिखें तो भी उनमें कई तरह के कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए हाथ को हमेशा साबुन से साफ करना चाहिए।
● सर्दी-जुकाम के दौरान छींक आने पर बड़ी संख्या में कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। यदि ये कीटाणु हमारे हाथों पर लग जायें और उन्हीं हाथों से हम अपने नाक, मुंह या आंख को छुएं तो हम भी तुरंत बीमारी की चपेट में आ जाएंगे।
● खाना बनाने के पहले, खाना खाने के पहले और शौच के बाद हाथ जरूर साफ करना चाहिए।
● दरवाजे की कुंडी और कीबोर्ड जैसी चीजों को छूने के बाद जरूर हाथ धोएं क्योंकि इन चीजों पर बड़ी संख्या में कीटाणु मौजूद होते हैं।

## हाथ कैसे करें साफ

● हाथ साफ करना वैसे तो बहुत आसान काम माना जाता है लेकिन इसके लिए भी कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है।
● साबुन और पानी के साथ हाथ को कम से कम 20 सेकेंड तक साफ करना चाहिए।
● यदि साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल मिला हुआ क्लींजर बेहतर विकल्प हो सकता है।
● एंटीबैक्टीरियल साबुन सेहत के लिए हमेशा अच्छे नहीं होते हैं।
● हाथ में पहने जाने वाले किसी भी आभूषण को हटाने के बाद गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए।
● हाथ साफ करते समय ऊंगलियों के बीच, नाखूनों और हाथ के दोनों तरफ सफाई करनी चाहिए।
● हाथ को रगड़ते हुए बहते पानी में धोना चाहिए।
● भीगे हाथों को हमेशा साफ तौलिये या कपड़े से साफ करें। जोर-जोर से हाथ पोंछने से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
● हाथ धोने के बाद नल को नैपकिन की सहायता से बंद करना चाहिए ताकि दोबारा नल बंद करने के दौरान हाथ कीटाणुओं के संपर्क में न आये।
● सार्वजनिक शौचालयों को इस्तेमाल करने के बाद भी दरवाजा खोलने के लिए नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए।

## खतरों को करें कम

● नाक साफ करते समय या छींकने के बाद अपने हाथ जरूर साफ करें।
● छींक आने के समय अपने हाथ मुंह पर न रखें। अगर टिश्यू पेपर मौजूद न हो तो अपनी बांह को मुंह के पास ले जाएं।
● अपने घर को हमेशा साफ रखें। दरवाजे की कुंडियां, लाइट स्वीच, टेलीफोन और की बोर्ड जैसी चीजों को नियमित रूप से साफ करें।
● छोटे बच्चों को अच्छे तरीके से हाथ धोने के बारे में बताएं।
● एक से ज्यादा बच्चों के हाथ पोंछने के लिए एक ही तौलिया इस्तेमाल में न लाएं।

**गौर कीजिए**

**पिछले बीस सालों में भारत सरकार ने स्वच्छता एवं पेयजल पर 1250 बिलियन राशि खर्च की है।**

चिंतनीय

# शौचालय : सवाल अस्मिता का

वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि पानी और शौचालय मानव अधिकार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी करोड़ों लोग इस मौलिक अधिकार से कोसों दूर हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.6 बिलियन लोग पर्याप्त साफ सफाई और शौचालय के बिना ही जीते हैं। इनमें से 1.1 बिलियन लोगों के पास शौचालय की कोई सुविधा नहीं है और वे खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वे खुले मैदान में, झाड़ियों में, रेलवे ट्रैक पर या प्लास्टिक बैग में शौच करते हैं। दुखद ये है कि खुले में शौच के नुकसान से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चियां होती हैं। न केवल उनकी शारीरिक जरूरतें पुरुषों के मुकाबले अलग होती हैं बल्कि उन्हें नहाने और शौच जाने के समय ज्यादा सुरक्षा की भी जरूरत होती है। ऐसा न होने पर बहुधा उन्हें छेड़छाड़ और बलात्कार तक की वारदातों का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छता और पेयजल पर काम कर रहीं विशेषज्ञ कैटरीना दि अलबकरक्यू बताती हैं कि अक्सर पानी और शौचालय की तलाश में दूर तक जाने वाली महिलाएं और लड़कियां यौन हिंसा की शिकार होती हैं। खासकर रात में इसका खतरा और बढ़ जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों महिलाओं और लड़कियों को शौच जैसी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने घर से 300 मीटर से ज्यादा दूर तक जाना पड़ता है। यही वजह है कि कई स्थानों पर मल को प्लास्टिक बैगों में बांधकर फेंकने का चलन है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शारीरिक रूप से असुरक्षित होने के अलावा खुले में शौच करने वाली महिलाओं को जंगलों और झाड़ियों के पीछे छिपे जानवरों का भी डर रहता है। खासकर ऐसे समय में सांप के काटे जाने की घटनाएं आम होती हैं। चूंकि पुरुष जानवरों पर पलटकर वार करने या चिल्ला कर लोगों को बुलाने में सक्षम होते हैं इसलिए उन्हें इसका खतरा कम रहता है लेकिन महिलाएं और बच्चियां आसानी से शिकार बन जाती हैं।

कैटरीना कहती हैं कि महिलाओं को शौचालय की जरूरत केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए ही नहीं होती बल्कि उनकी निजता की रक्षा के लिए भी यह बेहद जरूरी है। खासकर माहवारी के दिनों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा निजी और साफ स्थान की जरूरत होती है। कैटरीना इस बात पर अफसोस जताती हैं कि पीरियड के दिनों में महिलाओं की जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। यहां तक कि कई जगहों और संस्कृतियों में तो इन दिनों में महिलाओं और लड़कियों को पारिवारिक बहिष्कार तक का सामना करना पड़ता है। उन्हें घर से बाहर निकलने की मनाही कर दी जाती है और रोजमर्रा के कामों से अलग-थलग कर दिया जाता है। ऐसे में पहले से ही शौचालय की कमी का दंश झेल रही महिलाओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

भारत में स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था न होने का भी बहुत बड़ा असर पूरी शिक्षा पद्धति पर होता है। माता-पिता अपनी बच्चियों को प्राथमिक विद्यालय तक तो भेजते हैं लेकिन जैसे ही लड़की की माहवारी शुरू होती है, उसके स्कूल जाने पर रोक लगा दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय न होना है। यूएन विशेषज्ञ मानती हैं कि ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाई जाएगी। यहां तक कि घरेलू खर्चों को तय करने में भी महिलाएं अपनी मांगों को नहीं रख पातीं। यदि उन्हें मौका दिया जाय तो वे अपने लिए निजी शौचालय और स्नानघर बनवाये जाने को ज्यादा अहमियत देंगी।

**23 फीसद लड़कियां मासिक चक्र शुरू होते ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कई बार 66 फीसद लड़कियां इन दिनों स्कूल नहीं जातीं और उनमें से एक-तिहाई तो स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसके पीछे जो वजह छिपी है वो ये है कि करीब 40 फीसद स्कूलों में शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है जबकि लड़कियों के लिए अलग शौचालय तो बेहद कम स्कूलों में है।**

गौर कीजिए

देश में 44 फीसद माताएं अपने बच्चों को खुले में शौच करवाती हैं।

चिंतनीय

कैटरीना ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि एक बार एक पिता ने लगभग रोते हुए उनसे कहा था कि मेरी बेटी स्कूल नहीं जाना चाहती क्योंकि बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि उसके शरीर से बदबू आती है। पिता को मालूम है कि उसकी बेटी से बदबू आती है लेकिन वह मजबूर है क्योंकि सफाई के लिए उसके घर में पानी नहीं है।

कुछ समय पहले 'दासरा' ने देश में शौचालय की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दिल्ली के स्लम एरिया में सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने के दौरान 66 फीसद महिलाओं को अपमानजनक शब्दों का शिकार होना पड़ता है। 46 फीसद महिलाओं का पीछा किया जाता है और 30 फीसद महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी भारत में 50 मिलियन लोग हर रोज खुले में शौच करते हैं। इतना ही नहीं देश के कुल 5161 शहरों में से 4861 शहरों में आंशिक तौर पर भी सीवरेज नेटवर्क नहीं है। जाहिर है कि जब शहरों में स्वच्छता और शौचालय की स्थिति इतनी खराब है तो गांवों और गरीबों के लिए तो ये सुविधाएं दूर की कौड़ी हैं।

रिपोर्ट में शौचालय की कमी का पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले असर की भी व्याख्या की गई है। यह स्थिति तब है जब शौचालय की सुविधा के लिए शहरी गरीब अन्य शहरी लोगों की तुलना में 65 फीसद और ग्रामीण लोगों की तुलना में 75 फीसद ज्यादा भुगतान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो इसका सबसे बुरा असर देखने को मिलता है। लड़कियों के पढ़ाई छोड़ने के पीछे शौचालय का न होना बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक 23 फीसद लड़कियां मासिक चक्र शुरू होते ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं। कई बार 66 फीसद लड़कियां इन दिनों स्कूल नहीं जातीं और उनमें से एक-तिहाई तो स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। इसके पीछे जो वजह छिपी है वो ये है कि करीब 40 फीसद स्कूलों में शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है जबकि लड़कियों के लिए अलग शौचालय तो बेहद कम स्कूलों में है। 'दासरा' ने यह रिपोर्ट पटना सहित 15 शहरों में अध्ययन के आधार पर तैयार की है।

शहर और स्थान चाहे जो भी हों, औरतों की स्थिति हर जगह कमोबेश एक सी है। हरियाणा के मेवात जिले के हिरमाथला गांव में वर्ष 2011 तक एक भी शौचालय नहीं था। ऐसे में गांव की औरतों को शौच के लिए केवल दो बार बाहर निकलने की इजाजत होती थी। या तो तड़के अंधेरे में या फिर शाम को अंधेरा छाने के बाद। इस बीच में उन्हें खुद को नियंत्रण में रखना पड़ता था। वर्ष 2011 में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा चलाए गए अभियान के तहत गांव में शौचालय बनवाये जाने के बाद महिलाओं ने राहत की सांस ली। गांवों में खेतों या सड़क किनारे शौच के लिए जाने वाली महिलाओं को हूटिंग या छेड़छाड़ का भी शिकार होना पड़ता है। तड़के या

रात ढलने पर निकलने वाली महिलाओं को गाड़ियों की लाइट जलने पर शर्मसार होना पड़ता है। कई बार तो राहगीर उन पर पत्थर भी चला देते हैं। सर्दी और बरसात के दिनों में खुले में जाना बहुत दुश्कर और खतरनाक बन जाता है।

2011 में हुई जनगणना के मुताबिक, देश में 53.1 फीसद घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है जबकि ग्रामीण भारत में 69.3 फीसद घरों में शौचालय नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो लड़कियों की रेप के बाद हत्या के मामले ने देश को नयी दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि बाद में सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में लड़कियों के साथ रेप किये जाने की आशंका को खारिज कर दिया, फिर भी इस घटना से

**गौर कीजिए**

**बिहार सहित देश के सात राज्यों में पचास फीसद बच्चों को स्कूल में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं।**

शौच के लिए अकेले बाहर निकलने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार या छेड़छाड़ की आशंकाओं को ज्यादा बल मिला। उक्त वारदात के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि शौचालयों की संख्या बढ़ाकर देश में बलात्कार के मामलों में कमी लाई जा सकती है। इसी तरह राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कहा था कि शौचालय की कमी का महिलाओं से बलात्कार की घटनाओं से कोई सीधा संबंध चाहे न हो लेकिन ये सच है कि इससे महिलाओं तक पहुंच आसान हो जाती है। गांवों में अक्सर महिलाएं शौच के लिए घर से बहुत दूर जाती हैं। इससे न केवल उनकी सुरक्षा को खतरा होता है बल्कि उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। महिला आयोग ने कहा था कि वह शौचालयों की व्यवस्था कराने पर जोर देगा।

एक अखबार के साथ बातचीत में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ने बताया था कि पटना के नजदीक एक गांव में पार्वती देवी नाम की महिला ने वर्ष 2012 में अपना ससुराल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वहां शौचालय नहीं था। चार साल तक चली लड़ाई के बाद उसके ससुराल वालों ने शौचालय बनवाना मंजूर कर लिया। श्री पाठक मानते हैं कि सिर्फ पार्वती ही नहीं बल्कि अब बिहार के गांव-गांव में शौचालय की मांग कर रही बहू-बेटियों की तादाद बढ़ रही है। वे बताते हैं कि खुद उनके पैतृक घर में शौचालय नहीं था। जबकि उनका घर काफी बड़ा था और चारदीवारी के भीतर कुआं भी था लेकिन शौच के लिए लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता था। वे मानते हैं कि महिलाओं की असुरक्षा और मनुष्य की मर्यादा का सम्मान करने के लिहाज से उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की।

संयुक्त राष्ट्र की 2010 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में शौचालयों से ज्यादा मोबाइल की सुविधा मौजूद है। इसके अलावे भारत में हुए रिसर्च में भी कहा गया है कि वर्ष 2008 में सिर्फ 366 मिलियन लोगों (31 फीसद) को ही शौचालय की सुविधा प्राप्त है। वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र और जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद स्वच्छता की बात सोचने वाले हलकों में हड़कंप मच गया। तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने तब 'शौचालय नहीं, दुल्हन नहीं' का स्लोगन जारी किया। यह संदेश दिया गया कि जिन घरों में शौचालय न हों वहां लड़कियां न ब्याही जाएं। बहुत थोड़े पैमाने पर इसका असर हुआ और दो-चार लड़कियों ने शौचालय न होने पर ससुराल जाने से इंकार कर दिया। लकिन वृहत तौर पर देखा जाय तो शौचालय को लेकर आम लोगों की सोच में बहुत फर्क देखने को नहीं मिला।

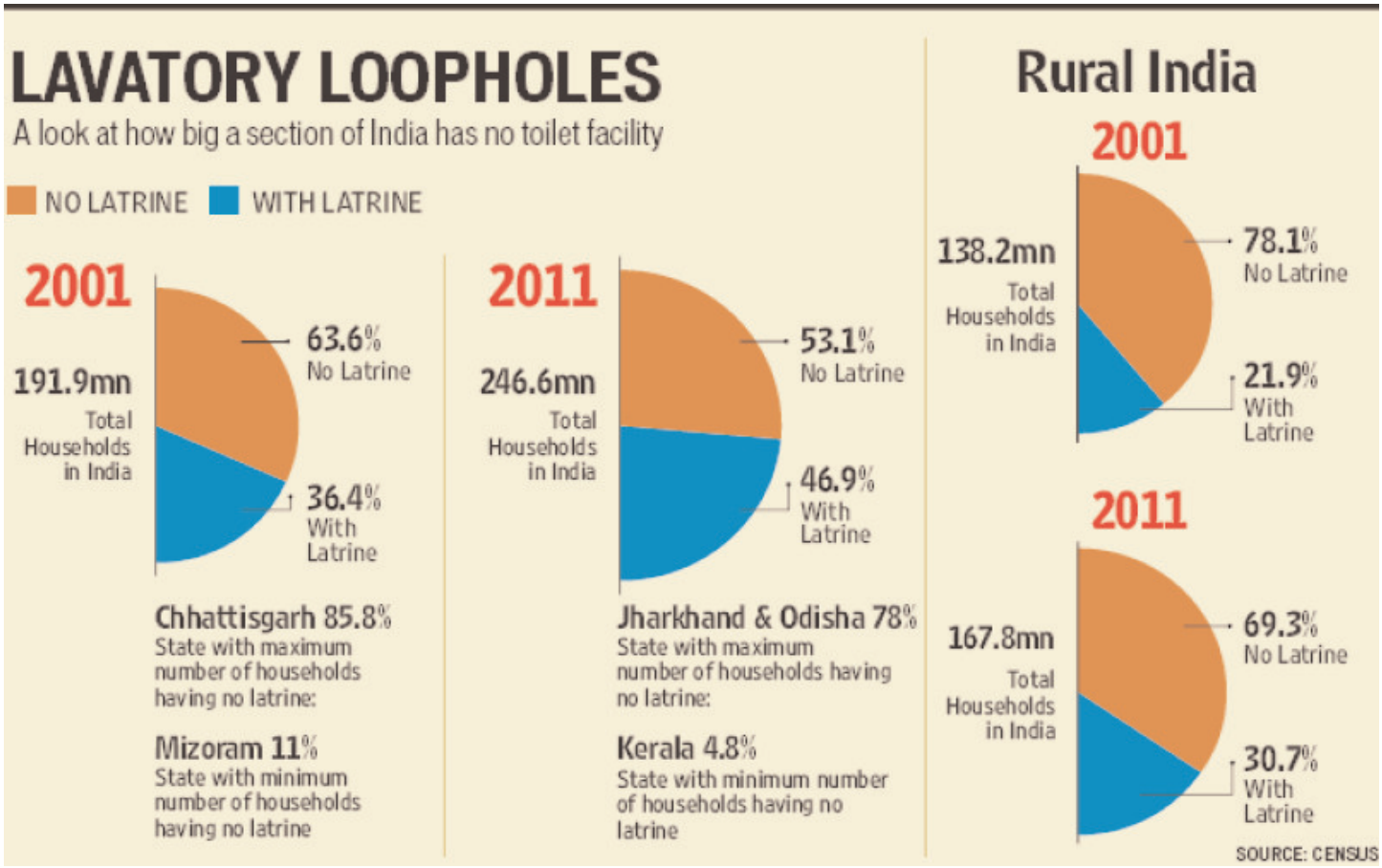


**गौर कीजिए**

**भारत में 23 फीसद लड़कियां मासिक चक्र के बारे में सही जानकारी न होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं।**

# चिंता में संयुक्त राष्ट्र भी

अस्वच्छ वातावरण और खुले में शौच करना, ये दो स्थितियां यूं तो हर एक जीव के लिए हानिकारक है लेकिन समाज का एक वर्ग जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, वो हैं महिलाएं। शौचालय का न होना मतलब एक लड़की का स्वस्थ न होना, शिक्षित न होना और सबल न होना। शौचालय होने का मतलब 1.25 बिलियन महिलाओं का स्वस्थ और सुरक्षित होना। शौचालय और साफ-सफाई न होने की वजह से हर रोज करीब दो हजार बच्चे डायरिया की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। शौचालय न होने की वजह से हर रोज हजारों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं और कामकाजी औरतें काम पर नहीं जा पाती हैं। शौचालय की कमी के कारण हर रोज हजारों लड़कियां और औरतें मासिक चक्र के दौरान संक्रमण का शिकार होती हैं। जाहिर है मुल्कों के विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसके लोगों को, महिलाओं और बच्चों को साफ वातावरण, स्वच्छ जल और शौचालय की सुविधा नहीं मिलेगी। दुनिया में अभी भी 2.5 बिलियन लोग खुले में शौच करते हैं, यानी हर तीन में से एक व्यक्ति शौचालय की पहुंच से दूर है। इन लोगों को

**शौचालय का न होना मतलब एक लड़की का स्वस्थ न होना, शिक्षित न होना और सबल न होना। शौचालय होने का मतलब 1.25 बिलियन महिलाओं का स्वस्थ और सुरक्षित होना।**

**गौर कीजिए**

**साबुन से हाथ धोने से हर रोज चार सौ से ज्यादा लोगों की जान बच सकती है।**

## ग्लोबल जिम्मेदारी

शौचालय तक पहुंचाना होगा लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने शौचालय की महत्ता को समझते हुए मिलेनियम डेवलेपमेंट गोल के तहत वर्ष 2015 तक पूरी दुनिया में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का लक्ष्य रखा था। समय समाप्ति की ओर है लेकिन लक्ष्य पहुंच से बहुत दूर है। इस चिंता को ध्यान में रख कर ही यूएन ने 19 नवम्बर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन दुनिया भर की सरकारों, नागरिक समाजों और स्थानीय निकायों को अब तक सबसे उपेक्षित रहे शौचालय की जरूरत के बारे में सोचने का मौका देगा। साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक विकास के बारे में एक सकारात्मक माहौल भी उत्पन्न करेगा। वर्ष 1990 से लेकर अब तक विश्व में करीब 1.9 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। लेकिन ये संख्या काफी नहीं है। अगर रफ्तार यही रही तो मिलेनियम गोल को तय कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि विश्व में अभी भी 45 ऐसे देश हैं जहां की आधी जनसंख्या शौचालय की पहुंच से काफी दूर है और उन्हें खुले में शौच के लिए बाध्य होना पड़ता है। दुनिया में हर साल करीब सात लाख बच्चे हर साल गंदे पानी और शौच करने के गंदे स्थान पर संक्रमण से होने वाले डायरिया की वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं। सात लाख बच्चे हर साल का मतलब है करीब दो हजार बच्चे रोज इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। यह आंकड़ा इस तथ्य को दर्शाने के लिए काफी है कि स्वच्छता और शौचालय की कमी का किसी देश की सेहत, सुरक्षा, सामाजिक ढांचे और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ता है। खासकर लड़कियों की शिक्षा पर तो इसका बेहद बुरा प्रभाव देखने को मिला है। मासिक चक्र के दिनों में शौचालय के न होने का जो खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है वह राष्ट्रीय शर्म की बात है। इतना ही नहीं इससे किसी भी देश को अपने आधे सक्षम कामगारों से हाथ धोना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 2013 में बुडापेस्ट में हुए जल सम्मेलन के दौरान यह स्पष्ट किया था कि शौचालय और स्वच्छता किसी भी देश के स्थायी विकास को दर्शाने के मापदंड माने जाएंगे। वर्ष 2015 तक संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य पूरा न होते देख बान की मून ने चिंता जताई और इसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज्यादा महत्व देने पर जोर दिया। श्री मून ने कहा कि सरकार एजेंसियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और औद्योगिक घरानों को एक साथ मिलकर इस ग्लोबल समस्या को दूर करने के उपाय तलाशने होंगे। दीर्घकालिक रणनीति को अपना कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शौचालय की सुविधा को पहुंचाने में कामयाबी मिल सकेगी। यही वजह है कि इस साल के विश्व शौचालय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया 'शौचालय संकट के शीघ्र, स्थायी और सहयोग आधारित समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल।'

### शर्मनाक सच

पूरे विश्व में 2.5 बिलियन लोग शौचालय विहीन है जिनमें से 526 मिलियन महिलाएं हैं जो खुले में शौच जाने को विवश हैं।

दुनिया में हर तीसरी महिला को शौचालय न होने के कारण शर्मनाक, खतरनाक और पीड़ादायक परिस्थिति से गुजरना पड़ता है।

शौचालय और स्वच्छता 1.25 बिलियन महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जिंदगी की ओर भेज सकती है।

शौचालय नहीं होने के कारण ऐसी महिलाओं और लड़कियों के हर साल 97 बिलियन घंटे शौच के लिए स्थान तलाशने में खर्च हो जाते हैं।

हर रोज 15 से लेकर 49 वर्ष तक की 800 मिलियन महिलाएं और लड़कियां मासिक चक्र से गुजरती हैं।

देश में 70.9 फीसद लड़कियों को मासिक चक्र शुरू होने के बारे में नहीं पता था।

इथियोपिया में एक अध्ययन में बताया गया कि करीब 50 फीसद लड़कियां मासिक चक्र के दौरान एक से लेकर चार दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं।

बांग्लादेश के कारखानों में कार्यरत महिलाओं पर हुए अध्ययन में पाया गया कि 60 फीसद महिलाएं मासिक चक्र के दौरान कारखाने में प्रयोग में लाये जाने वाले कालीनों का इस्तेमाल करती हैं।

**दुनिया में हर साल करीब सात लाख बच्चे गंदे पानी और शौच करने के गंदे स्थान पर संक्रमण से होने वाले डायरिया की वजह से मौत के मुंह में समा जाते हैं। सात लाख बच्चे हर साल का मतलब है करीब दो हजार बच्चे रोज।**

**गौर कीजिए**

**साबुन से हाथ धोने से संक्रमण को 23 फीसद तक कम किया जा सकता है।**

ग्लोबल जिम्मेदारी

# विशेषज्ञों को है दायित्व का अहसास

19 नवम्बर, 2014 यानी विश्व शौचालय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेषज्ञों ने शौचालय और स्वच्छता की कमी का महिलाओं पर पड़ने वाले दुष्परिणामों पर गहनता से चर्चा की। अपने संदेश में इन विशेषज्ञों ने महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा, सेहत और सभी पहलुओं पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले कारक की पहचान कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। ये बताया कि शौचालय की मौजूदगी न केवल उनकी निजता के लिए जरूरी है बल्कि यह अब उनका मौलिक अधिकार भी बन चुका है। जेनेवा में आयोजित इस चर्चा में संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर कैटरीना दि अलबकरक्यू, राशिदा मंजू और मउद दि बोअर बुकीचिओ शामिल रहे। चर्चा में यह बात साफ तौर पर उभर कर आई कि शौचालय के न होने से महिलाओं और बच्चियों के सम्मान पर आंच आती है और यह बच्चों और महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उनकी खरीद-बिक्री के लिए भी बड़ा उत्तरदायी कारण बन जाता है। अगर शौचालयों की व्यवस्था करा दी जाय तो आंकड़े कुछ और ही होंगे।

## टैबू है मासिक चक्र के बारे में बात करना

कैटरीना दि अलबकरक्यू ने बताया कि अपने संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान अब तक वे बिल्कुल अलग-अलग संस्कृतियों वाले 15 देशों का दौरा कर चुकी हैं और जहां भी वे गईं लगभग हर जगह उन्होंने पाया कि महिलाओं को अपनी साफ-सफाई और शौच की जरूरत के लिए बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई देशों में तो वहां की संस्कृति और परंपरा के कारण औरतों और लड़कियों को उन सुविधाओं से वंचित रखा जाता है जिसे उनके पुरुष साथी या रिश्तेदार इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी महिला के ससुर यदि शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो महिला को उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। इसी तरह कई देशों में महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान घरों में मिलने वाली आम सुविधाओं का भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। महीने के कम से कम छह दिनों के लिए न तो उन्हें बिस्तर पर सोने की अनुमति होती है और न ही घर के कई हिस्सों, जैसे-रसोई या पूजा के स्थान पर जाने की इजाजत। एक तरह से मासिक चक्र के दौरान महिलाओं और लड़कियों को बेहद कठिन सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैटरीना ने बताया कि अपनी यात्राओं के दौरान वे हमेशा लड़कियों की माहवारी से संबंधित जानकारियों और साफ-सफाई के बारे में बात करना चाहती हैं लेकिन उन्होंने पाया कि इस बारे में बात करना लगभग पूरी दुनिया में शर्म की बात मानी जाती है। माहवारी के दौरान महिलाओं और लड़कियों को अशुद्ध, गंदी और वर्जित माना जाता है। यही कारण है कि माहवारी के दौरान की औरतों की जरूरतों के बारे में न तो ध्यान दिया जाता है और न ही परिवार का बजट तय करने के दौरान इसके लिए अलग से कोई खर्च किया जाता है। नतीजा महिलाओं और किशोरवय लड़कियों को माहवारी के दौरान बहुत ही कठिन और शर्मनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें अपने शरीर से बदबू आने या दाग लगने का डर रहता है और इस वजह से वे स्कूल-कॉलज या काम के स्थान पर जाने से परहेज करती हैं।

## सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण बेहद जरूरी

कैटरीना की तरह राशिदा मंजू ने भी अपने अनुभवों और अध्ययन को साझा किया। उन्होंने शौचालय की कमी का असर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। राशिदा ने बताया कि वर्ष 2014 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक अभी भी एक बिलियन से ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं और महिलाओं और बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। महिलाओं और बच्चियों को उत्पीड़न, अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता है जब उन्हें सार्वजनिक शौचालय या खुले में शौच करने के लिए बाध्य किया जाता है। यदि घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो महिलाओं और छोटी बच्चियों के प्रति होने वाली हिंसा में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। राशिदा के मुताबिक स्वच्छ शौचालय का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है लेकिन इसके साथ ही यह महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के एक उपाय के तौर पर भी जाना जा सकता है। कई देशों में जिनमें भारत भी शामिल है, शौच के लिए निकली महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं अक्सर सुर्खियां बनती हैं। राशिदा ने बताया कि अगर किसी कारणवश घरों में शौचालय बनवाना संभव नहीं भी हो तो कम से कम सार्वजनिक शौचालयों का सुरक्षित होना जरूरी है ताकि न केवल महिलाओं की निजता और शुचिता को सुरक्षित रखा जा सके बल्कि पूरे समाज की सेहत को बुलंद रखा जा सके। सार्वजनिक शौचालय बना दिये जाने से भी बहुत हद तक समस्या को कम किया जा सकता है।

ग्लोबल जिम्मेदारी

## समझा जाने लगा शौचालयों का महत्व

संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छता और शौचालय का महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न पर पड़ने वाले असर पर अध्ययन करने वाले मउद बुकीचिओ ने बताया कि विश्व भर में अब शौचालय के महत्व को समझा जाने लगा है और सरकारों ने इसके लिए प्रयास करने शुरू कर दिये हैं। जहां निजी शौचालय नहीं बनवाये जा सकते हैं वहां सार्वजनिक शौचालय बनवाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन देशों की अपनी परंपराओं के कारण महिलाओं को उन शौचालयों में भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। महिलाओं और बच्चों के लिए पहले से ही असुरक्षित समाजों में ऐसे निषेध उन्हें यौन उत्पीड़न करने वाले के हाथों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। मउद जोर देकर कहते हैं कि महिलाओं को ऐसी कुरीतियों और माहौल से बचाने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने का जो दंड लड़कियों को भुगतना पड़ता है वह उन्हें आजीवन दुख देता रहता है। किशोरावस्था में कदम रखते ही लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वहां उनके लिए अलग शौचालय नहीं होते। माहवारी के दिनों में होने वाली मुश्किलों का कोई समाधान नहीं होने के कारण मां-बाप अपनी बेटियों का स्कूल बंद करवाना बेहतर समझते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी की शादी करवाने की चिंता ज्यादा सताने लगती है और भारत सहित कई देशों में 15 से 20 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करा दी जाती है और उनके अपने बच्चे होने लगते हैं। जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनके मन में अपनी अनपढ़ मां के लिए सम्मान नहीं होता। अक्सर गांव के लड़के वयस्क होने पर शहरों की ओर रुख करते हैं लेकिन उनके मन में होता है औरतों के प्रति असम्मान का भाव जो कई बार छेड़छाड़ और दुष्कर्म का रूप में सामने आता है। यानी एक शौचालय की कीमत उन्हें पूरी जिंदगी की आजादी गंवाकर चुकानी पड़ती है। शौचालय के न होने का इससे बड़ा दुष्परिणाम क्या होगा कि बिहार में पिछले साल दर्ज रेप की घटनाओं में से पचास फीसद उस समय घटित हुई जब महिलाएं या बच्चियां अंधेरा होने के बाद शौच के लिए घर से बाहर निकली थीं।

- शौचालय और साफ-सफाई की व्यवस्था महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान ज्यादा सुरक्षित, स्वास्थ्यजनक व सम्मानजनक माहौल दे सकती है।
- सफाई नहीं होने के कारण महिलाओं में बड़े पैमाने पर संक्रमण पाया गया जिसके कारण 73 फीसद महिलाएं महीने के कम से कम छह दिनों तक काम से अनुपस्थित रहती हैं।
- महिला कामगारों के काम से अनुपस्थित रहने के कारण कारखाना मालिकों के आर्थिक लाभ में कम से कम तीन फीसद का नुकसान होता है।
- अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्रों में लड़कों के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पूरी करने की दर 56 फीसद है जबकि लड़कियों के 46 फीसद।
- अल्पविकसित देशों में केवल 45 फीसद स्कूलों में ही शौचालय की समुचित व्यवस्था होती है।
- बांग्लादेश में स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था कराने की एक योजना के बाद लड़कियों के दाखिले में 11 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई।
- केन्या में स्कूलों में शौचालय बनवाने की योजना के बाद बच्चों में डायरिया के मामलों में 50 फीसद तक की कमी देखी गई।
- साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर रोज करीब दो हजार माताओं को डायरिया की वजह से अपने बच्चों को खोना पड़ता है।

**गौर कीजिए**

**राज्यों में हर व्यक्ति के लिए रोज पचास से सौ लीटर पानी की जरूरत है।**

दृष्टिकोण

# हरेक के लिए एक शौचालय

जयराम रमेश

(पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री)

उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों की हत्या का मामला जाति और लिंग आधारित अपराध की श्रेणी में आता है लेकिन यह खुले में शौच करने और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, निजता और उनकी मर्यादा से जुड़े मामले की श्रेणी में भी आता है। चुनाव बीत चुके हैं। आदर्शों और व्यक्तियों के बीच का संघर्ष खत्म हुआ। जनता ने मजबूत फैसला सुनाया है। नई सरकार धीरे-धीरे अपने एजेंडे को देश के सामने रख रही है। आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक दलों को एक साथ ला सकते हैं। अति दूषित पर्यावरण और घरेलू स्वच्छता ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए राजनीतिक दल एकजुट हो सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमने इसी हालात में जीना सीख लिया है। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि देश में 600 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। यह संख्या दुनिया में सर्वाधिक है। ऐसे में भारत जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, 2015 के ज्यादातर लक्ष्यों को पाने में सफलता की ओर बढ़ रहा है वहीं स्वच्छता के लक्ष्यों को पाने में यह बुरी तरह नाकाम हो सकता है। यह अस्वीकार्य और शर्मनाक है।

दुख की बात है कि दर्दनाक बदायूं मामला इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के अपराध मानवाधिकारों के पतन को बयां करते हैं। शौच तक करने के लिए सुरक्षित स्थान का न होना बच्चियों और महिलाओं की निजता, सुरक्षा और गरिमा पर प्रहार है। महिलाओं चाहे वे बेटी, मां या बहन हों, की सुरक्षा और सशक्तीकरण का सबसे आसान तरीका है घर में शौचालय की व्यवस्था करना। इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो गंदगी की वजह से हमारा देश एक नये खतरे की ओर बढ़ रहा है जिसे विशेषज्ञों ने 'पर्यावरणीय संक्रमण' का नाम दिया है। यह खतरा हमारे देश में कुपोषित बच्चों की लगातार बढ़ रही संख्या की ओर इशारा करता है जिससे क्रमशः बच्चों में कई तरह की क्षमताओं का ह्रास होता जा रहा है।

हर रोज 20 मिलियन से अधिक यात्रियों को ढोने वाला भारतीय रेलवे अतार्किक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा खुला शौचालय है। दावों के बावजूद मैला ढोने की प्रथा अभी भी हमारे देश के माथे पर एक बदनुमा दाग है क्योंकि करीब 2.6 मिलियन सूखे शौचालय अभी भी देश में मौजूद है। तमाम उपायों के बाद भी हमारी पवित्र नदियां, खासकर गंगा और यमुना गंदे पानी के विशालकाय नाले बन कर रह गई हैं। केंद्र में सत्ता पाने वाली हर सरकार ने इस समस्या से निपटने की कोशिश की है। वर्ष 1986 में देश में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को अपनाया गया और अब 2012 में निर्मल भारत अभियान का नारा दिया गया है। बजटों में स्वच्छता पर खर्च को पहले से ज्यादा जगह दी जाने लगी है, हालांकि अभी भी यह काफी कम है। संत गाडगे महाराज की प्रेरणा पाकर महाराष्ट्र व कुछ अन्य राज्यों ने स्वच्छता और शौचालय के क्षेत्र में खुद पहल करते हुए अच्छी मिसाल कायम की है। यहां का कोल्हापुर जिला खुले में शौच से मुक्त जिला बनने की ओर अग्रसर है। इसी तरह सिक्किम और केरल में खुले में शौच की गलत प्रथा करीब-करीब खत्म हो चुकी है तो हिमाचल प्रदेश सामुदायिक उत्प्रेरण के जरिये सफलता की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी उम्मीद से बढ़कर काम देखने को मिल रहे हैं। 2013-14 में मनरेगा के तहत किये गये कुल कामों में से 28 फीसद काम सिर्फ शौचालय निर्माण के क्षेत्र में किये गये जबकि एक मिलियन शौचालय अकेले बिहार में ही बनाये जाने का लक्ष्य है। तिरूचिरापल्ली देश का पहला खुले में शौच से मुक्त नगर निगम बन गया है। स्वयंसेवी संगठनों की भी इस दिशा में सराहनीय भूमिका रही है। सुलभ इंटरनेशनल देश भर में और खासकर शहरी क्षेत्रों में एक मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण और संचालन कर रहा है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किये गये नये बायो शौचालयों को ट्रेनों के नये कोचों में लगाया जाना है। इसी तरह महिलाओं में भी जागरूकता बढ़ रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है मध्य प्रदेश के बैतूल की आदिवासी महिला अनीता बाई नारे, जिसने शादी के बाद अपना ससुराल इसलिये छोड़ दिया क्योंकि वहां शौचालय नहीं था।

देश की करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों में से करीब 12 फीसद को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, हालांकि वे पंचायतें खुले में शौच से कितनी मुक्त हैं, इस पर सवाल उठाये जाते रहे हैं। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने विश्व की वैज्ञानिक और तकनीकी बिरादरी को भारत के लिए कम बजट वाले शौचालय बनाने की चुनौती दी है। इन तमाम कामों के बाद भी अपने लक्ष्य को पाने की तरफ हम बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं।

**गौर कीजिए**

**बिहार में केवल एक फीसद लोग स्वास्थ्य के लिए शौचालय की सुविधा चाहते हैं।**

दृष्टिकोण

**खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करने के लिए देशवासियों में अब जुनून पैदा करने की जरूरत है। एक ऐसे सामाजिक बदलाव को लाना होगा जो हर आदमी, चाहे वह किसी भी जाति, राजनीतिक दल या लिंग का हो, को इस अभियान में साथ चलने के लिए उद्वेलित कर दे।**

इस साधारण सी सच्चाई को हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि देश की सेहत को पटरी पर लाने के लिए साफ पेयजल और स्वच्छता सबसे अच्छा और सस्ता निवेश है। इसके लिए जरूरत है सरकार के सहयोग से आम लोगों को प्रेरित कर सामाजिक क्रांति लाने की। खुले में शौच को पूरी तरह समाप्त करने के लिए देशवासियों में अब जुनून पैदा करने की जरूरत है। एक ऐसे सामाजिक बदलाव को लाना होगा जो हर आदमी, चाहे वह किसी भी जाति, राजनीतिक दल या लिंग का हो, को इस अभियान में साथ चलने के लिए उद्वेलित कर दे। देश में चल रहे ग्रामीण स्वच्छता अभियानों को और ज्यादा विस्तारित करना होगा जबकि शहरी, उपनगरीय व अर्द्धनगरीय स्वच्छता अभियानों को ज्यादा आजादी और तीखापन देना होगा। लोगों की मानसिकता बदलने के प्रयासों के साथ-साथ शौचालयों का निर्माण रफ्तार के साथ करना होगा। नीतियां बनानी होंगी और इनाम तथा सजा के प्रावधान एक साथ लागू करने होंगे। लेकिन पानी की बर्बादी और कचरे के प्रबंधन पर भी साथ-साथ ध्यान देना होगा। करीब पचास हजार रेलवे कोचों में बायो शौचालयों को लगाने का काम भी पांच साल के भीतर ही पूरा करना होगा। देश में तेजी से फैल रहे महिला स्वयं सहायता समूहों में पोषण आधारित कार्यक्रमों के तहत स्वच्छता को भी मुख्यधारा में लाना होगा। इस मामले में तमिलनाडु ने अच्छी पहल की है जहां के महिला स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं और किशोरियों के लिए सस्ते सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सहायता प्राप्त इन महिला समूहों को 'शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं' जैसे अभियानों की शुरूआत कर उनका प्रसार करना चाहिए। वर्ष 2012 में देश के कई राज्यों में शुरू निर्मल भारत यात्रा और उड़ीसा में ग्राम विकास तथा बिहार में सखी जैसे संगठनों के कामों से प्रेरणा लेकर एनजीओ को भी इस क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर आगे आना चाहिए। अलग-अलग धाराओं से आने वाले ब्रांड अम्बेसडरों को भी स्वच्छता के संदेशों को प्रचारित करना चाहिए। विद्या बालन और सचिन तेंदुलकर के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। सोशल मीडिया और मुख्यधारा की मीडिया को भी इसमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका चुने हुए जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए जो लोगों को प्रभावित करने, उन्हें प्रेरित करने और परिणाम आधारित अभियान चलाने में सक्षम हैं। इसकी शुरुआत एक संसदीय फोरम बनाकर की जा सकती है जिसके आधार पर राज्यों में भी फोरम की स्थापना की जा सके।

पांच साल के बाद देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएगा। कितना अच्छा हो अगर सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी मुख्यमंत्री और सभी स्थानीय निकायों के प्रमुख राजघाट पर एकत्र होकर शपथ लें कि वर्ष 2019 तक देश खुले में शौच के कलंक से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपिता को इससे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि भला और क्या हो सकती है। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम है और खासकर उत्तर भारत में इतने कम समय में ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन है, फिर भी बड़े और मजबूत इरादों के साथ अगर हम काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियानों के दौरान 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा दिया था जो कभी नहीं हो सकता। अब जबकि वे प्रधानमंत्री बन गये हैं तो उन्हें 'खुले में शौच मुक्त भारत' का नारा देना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर पार्टी के लोग उनके साथ हाथ मिलाकर चलेंगे।

**(6 जून, 2014 को इंडिया टुडे में प्रकाशित आलेख)**

**गौर कीजिए**

**बिहार में कम वजन वाले बच्चों की बहुतायत है जो पूरे देश का पंद्रह फीसद है।**

# शौचालय : एक छिपी हुई समस्या

शौचालयों की कमी का खामियाजा शहरी और ग्रामीण, दोनों इलाकों में रहने वाली महिलाओं को समान रूप से भुगतना पड़ता है। शौचालय नहीं रहने के कारण महिलाएं अंधेरा होने के बाद ही घर से बाहर शौच के लिए निकल पाती हैं क्योंकि दिन में खुलेआम देखे जाने का खतरा वे नहीं मोल ले सकतीं। बेंगलुरू के बाहरी इलाके के एक विस्थापन शिविर में रहने वाली मुन्नी के लिए शौचालय न होना इतना महंगा पड़ा कि उसने अपने खाने-पीने का समय तक बदल दिया है। उसने खाना कम कर दिया है और भोजन से खुद को दूर कर लिया है। मुन्नी बताती है "हां मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन अगर मैं खाना खाऊंगी तो उसके पचने के बाद मुझे शौचालय जाने की जरूरत पड़ेगी। इस शिविर में महिलाओं के लिए केवल दो शौचालय हैं जिसकी वजह से वहां हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। इसलिए मैं दिन में केवल एक बार ही खाती हूं ताकि मुझे केवल एक बार ही शौचालय जाने की जरूरत महसूस हो।" मुन्नी की ही तरह ऐसी तमाम महिलाएं और लड़कियां जिन्हें शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ने अपने खाने-पीने की आदतों को बदल दिया है। अंधेरा होने पर शौच के लिए जाने की मजबूरी में ये औरतें और बच्चियां कब्ज, अपच और पानी की कमी जैसी समस्याओं की शिकार हो जाती हैं जो कई बार गंभीर बीमारियों को न्योता देती हैं। आंध्र प्रदेश के एक स्वयंसेवी संगठन के साथ काम कर रहे डा. अलमास अली ने बताया कि महिलाओं में गाइनी संबंधी और पेशाब नली में संक्रमण जैसी बीमारियां उन जगहों की औरतों में ज्यादा पाई जाती हैं जहां शौचालय उपलब्ध नहीं होता। अध्ययनों में पाया गया है कि शौचालय की सुविधा न होना ही एकमात्र समस्या नहीं है बल्कि उपलब्ध शौचालयों का इस्तेमाल न करना भी बड़ी मुसीबत है। यानी केवल गरीबी ही नहीं बल्कि लोगों की आदत भी इसके लिए जिम्मेदार है।

**-शकुंतला नरसिम्हन**

**(शकुंतला बेंगलुरू में वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका यह आलेख इंडिया सैनिटेशन पोर्टल पर जुलाई, 2002 में प्रकाशित हुआ था)**

# मानव मल व गंदगी से जंग खा रहीं पटरियां

सुबह-सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे घूमने निकले लोगों को एक दृश्य का सामना रोज करना पड़ता है। वह है ट्रैक के किनारे शौच करने वाले लोगों का झुंड। बहुत हद तक शौचालय की कमी इसके लिए जिम्मेदार है तो कुछ हद तक लोगों की आदतें भी। देश के किसी भी रेलवे ट्रैक पर यह दृश्य आम है। पटरियों पर शौच करने के बाद लोग तो अपने-अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं खतरा। वो खतरा जो कभी भी उस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों की जान आफत में डाल सकता है। वर्ष 2012 में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि गंदगी के कारण पटरियां जंग खाती जा रही हैं। यह गंदगी न केवल रोज पटरियों पर शौच करने के कारण होती है बल्कि ट्रेनों में शौचालय का इस्तेमाल के कारण भी होती है। हर रोज करोड़ों लोग भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं और इस दौरान ट्रेन में मौजूद शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी का नतीजा है कि देश में फैले 64,400 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर हर जगह मानव मल फैला हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव गंदगी के कारण न केवल पटरियां जंग खा रही हैं बल्कि अन्य संरचनाओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावे गंदगी के कारण पटरियों का निरीक्षण भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता जिसका खामियाजा रेलवे को भुगतना पड़ता है। वर्ष 1999-2000 की रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि मानव मल के कारण पटरियां इतनी गंदी हो जाती हैं कि उनका नियमित निरीक्षण कर पाना भी संभव नहीं होता। इसी तरह रेलगाड़ियों में सफर कर रहे यात्री बार-बार की अपील के बाद भी ट्रेनों के रुकने के बाद भी शौचालय का इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। ऐसे में गंदगी सीधे ट्रैक पर गिरती है जो हर तरह से खतरनाक है। पैलेस ऑन व्हील्स जैसी कुछ महंगी ट्रेनों, जिनमें बेहतरीन शौचालय की व्यवस्था मौजूद है, को छोड़कर अन्य ट्रेनों में साधारण शौचालय ही मौजूद हैं। हालांकि रेलवे ने अगले पांच सालों में ट्रेनों में बेहतर शौचालय फिट करने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक अनिल काकोदकर के मुताबिक इस पर कुल तीस बिलियन का खर्च आएगा।

# खुले में शौच की प्रवृत्ति सांस्कृतिक विकृति

**बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु में 60 फीसद से ज्यादा घर अभी भी बिना शौचालय के हैं।**

क्या किसी को इस बात पर आश्चर्य होगा कि भारत के 1.2 बिलियन आबादी में से आधी आबादी के घर में शौचालय नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत की मानव विकास सूचकांक ने ये आंकड़े पेश किये हैं। गांवों में हालात और खराब हैं जहां दो-तिहाई घरों में शौचालय मौजूद नहीं हैं। खुले में शौच करने की परंपरा कायम है और यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को पाने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। लक्ष्य के मुताबिक 2015 तक देश में खुले में शौच करने वाली आबादी की संख्या आधा करना है।

क्या भारत में शौचालयों की कमी और खुले में शौच करने की आदत एक सांस्कृतिक मुद्दा है क्योंकि अभी भी देश में सिर पर मैला ढोने वालों की छोटी संख्या मौजूद है ? शायद हां। एक लेखक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शौचालयों की सफाई के लिए हमेशा चिंतित रहने वाला व्यक्ति करार दिया था। एक बार जब गांधी गुजरात के राजकोट में शौचालयों का निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने एक मंदिर और एक धनी व्यक्ति के शौचालय के बारे में कहा था कि उनके शौचालय अंधेरे, गंदे और कीड़ों से भरे हुए थे। अछूतों के घर में तो शौचालय होते ही नहीं थे। एक बार एक हरिजन ने गांधी जी से कहा था "शौचालय आप जैसे बड़े लोगों के लिए होते हैं।" बहुत साल बाद जब गांधी ने अपने सहयोगियों को स्वच्छता अधिकारी और सफाईकर्मी की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया तो उस समय के अनुभवों को उनके करीबी सचिव रहे माधव देसाई ने लिखा कि गांव वालों के मन में हमारे लिये कोई भावना नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दिनों के बाद गांव वाले हमें मैला ढोने वाले समझने लगें। भारत को शर्मसार करने वाली इस समस्या की जड़ इसकी संस्कृीत से जुड़ी है। आजादी के आधी सदी बाद भी ज्यादातर अपने घरों को साफ रखते हैं और शौच के लिए खुले स्थान का इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि धीरे-धीरे ही सही मगर गांवों में स्थिति सुधर रही है। 2002 में जहां केवल 40 फीसद लोगों की पहुंच शौचालय तक थी वह 2008-09 में बढ़कर 51 फीसद तक पहुंच गई। लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु में 60

फीसद से ज्यादा घर अभी भी बिना शौचालय के हैं। साफ-सफाई के प्रति लोगों की आदतों में धर्म और जाति का असर भी देखा गया है। एक अध्ययन में पाया गया कि सिख और ईसाइयों के 70 फीसद घरों में शौचालय हैं जबकि हिंदुओं के महज 45 फीसद घरों में यह सुविधा मौजूद है। यह स्थिति तब है जबकि केंद्र सरकार शौचालय बनवाने के लिए लोगों को सब्सिडी तक का भुगतान करती है। 2005 में स्वच्छता पर होने वाले खर्च को भी तीन गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया। वर्ष 2003 में सरकार ने खुले में शौच मुक्त पंचायतों को सम्मान देने की शुरुआत की और इसका पहला विजेता बना केरल जहां के 87 फीसद ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गईं। दूसरी ओर बिहार के केवल दो फीसद पंचायत ही इस सम्मान के लिए चुनी जा सकीं। हालांकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य बने जिन्होंने अपने लोगों को प्रेरित कर इस दिशा में अच्छी कामयाबी हासिल की।

**शौतिक विश्वास , पत्रकार, बीबीसी**

**(16 मार्च, 2012 को बीबीसी में प्रकाशित)**

**गौर कीजिए**

**एक लड़ाकू विमान की कीमत एक हजार गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए काफी है।**

भारी पड़ती गंदगी

# गरीब करते हैं गंदगी का भुगतान

गंदगी समाज के लिए बुरा है, सेहत के लिए खतरनाक है मगर अर्थव्यवस्था के लिए बेहद नुकसानदायक है। 2006 में वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम द्वारा भारत में किये गये ग्लोबल इकोनॉमिक्स ऑफ सैनिटेशन इनीशियेटिव (ईएसआई) नामक अध्ययन के बाद पाया गया कि शौचालय और स्वच्छता न होने का बहुत बुरा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अध्ययन में मुख्य रूप से मानव मल का प्रबंधन और स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में उसके दुष्परिणाम की व्याख्या की गई है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संयुक्त निगरानी कार्यक्रम के तहत स्वच्छता का मतलब है मानव मल को मनुष्य के संपर्क से दूर रखना ताकि स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों को कम किया जा सके। इस तरह समुचित सफाई न होने का मतलब शौचालय की सुविधा न होना और स्वच्छता के अन्य उपायों जैसे-हाथ धोना, शुद्ध पानी और खुद की सफाई न रखना है। साफ-सफाई की कमी से लोग मरते हैं, बच्चे बीमार होते हैं और महिलाएं असुरक्षित होती हैं, ये तथ्य तो सब जानते हैं लेकिन ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं कि साफ-सफाई की कमी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर 2.44 ट्रिलियन रुपये का भार पड़ता है। यह राशि वर्ष 2006 के कुल जीडीपी का 6.4 फीसद है। ईएसआई अध्ययन में स्वच्छता के सभी आयामों के प्रभावों को देखा गया है। इनमें शौचालय की उपलब्धता और उसकी सफाई, उसके पानी की उपलब्धता और उसके रख-रखाव का स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादकता और पर्यटन पर असर को रखा गया है। अध्ययन के मुताबिक भारत में समुचित साफ-सफाई न होने की वजह से बच्चों का समय पूर्व जन्म लेना व अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर सबसे ज्यादा 38.5 बिलियन डॉलर का खर्च किया जाता है। इसके अलावा शौच के लिए जगह ढूंढने में उत्पादकता के समय में भारी कमी होती है जिसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होता है और 10.7 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इसके बाद पीने के पानी के लिए मीलों चल कर जाने और शुद्ध पानी की उपलब्धता न होने से होने वाली बीमारियों का असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है और इसमें 4.2 बिलियन डॉलर का खर्च हो जाता है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बरसों से हम भारत में व्याप्त गंदगी का वहां के लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर के बारे में पढ़ते आये हैं लेकिन अंततः इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर कितना होता है इसके बारे में बहुत कम शोध किये गये हैं। कुल मिलाकर गंदगी का भुगतान भारत की गरीब जनता ही करती है।

अध्ययन में पाया गया कि देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत सबसे ज्यादा डायरिया के कारण होती है। गंदगी डायरिया का बड़ा कारण है और इससे बचने के प्रयास एवं इससे होने वाली मौत से नुकसान करीब 47 फीसद यानी 824 बिलियन रुपये के बराबर होता है। अध्ययन में इस बार पर जोर दिया गया कि सरकार को शौचालय व अन्य स्वच्छता अभियानों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि सरकार को न केवल देश में शौचालयों की संख्या और उनके उपयोग की दर पर ध्यान देना चाहिए बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था व समाज पर होने वाले उसके प्रभावों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अध्ययन में यह बात सामने आई कि यदि शौचालय व अन्य सफाई के तरीकों को अपनाया जाय तो देश 1.48 ट्रिलियन पैसे की बचत कर सकता है। इसके अलावे यदि लोग इन विषयों में रुचि लें और इनसे जुड़ें कामों में निवेश करें तो 6.87 ट्रिलियन तक का फायदा हो सकता है।

**एक ग्राम मल में एक करोड़ वायरस, एक लाख बैक्टीरिया, एक हजार परजीवी सिस्ट और एक सौ परजीवियों के अंडे होते हैं। (डब्ल्यूएचओ)**

**गौर कीजिए**

**भारत में स्वच्छता पर कुल जीडीपी का 0.02 फीसद खर्च किया जाता है।**

भारी पड़ती गंदगी

# गंदगी + खुले में शौच = कुपोषण व छोटा कद

भारतीय बच्चे दुनिया के तमाम पिछड़े देशों के बच्चों की तुलना में सबसे ज्यादा कुपोषित क्यों होते हैं। यह सवाल लंबे समय से शोधकर्ताओं के लिए शोध का विषय रहा है। अब तक विश्व के लगभग सभी देशों ने कुपोषण के लिए पोषणयुक्त भोजन और साफ पानी को ही जिम्मदार माना और उनका शोध भी इसी के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। लेकिन अब यूनिसेफ सहित अन्य एजेंसियों ने भी कुपोषण के लिए पानी के अलावा शौचालय और स्वच्छता की ओर ध्यान देना शुरू किया है। यूनिसेफ के पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य यूनिट के प्रमुख सु कोट्स के मुताबिक स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध की अवधारणा नई है। इस क्षेत्र में पहले बहुत कम सोचा गया था। अब एक नये शोध में यह बात सामने आई है कि छोटे बच्चों में कुपोषण के पीछे खुले में शौच करने और जहां-तहां मल करने से हुए प्रदूषण का बड़ा हाथ है।

शोध के मुताबिक भारत में जन्मा एक बच्चा विश्व के सबसे गरीब देशों कांगो, जिम्बाब्वे या सोमालिया में जन्मे एक बच्चे की तुलना में कहीं ज्यादा कुपोषित होता है। क्यों? देश के पांच साल से कम 65 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनमें से एक तिहाई बच्चे अमीर घरों के हैं। इस तथ्य ने आर्थिक विश्लेषकों को इतना चौंका दिया कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि आर्थिक उन्नति कुपोषण को दूर करने में मदद नहीं करती।

देश की आधी जनसंख्या मतलब करीब 620 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि जिस दर से हर साल देश की आबादी में इजाफा होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के गंदगी और मल के संपर्क में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार के शिवहर में साल 2001 से लेकर 2011 के बीच घरों में शौचालयों की संख्या जरूर बढ़ी लेकिन आबादी के बढ़ने की दर के आगे ये प्रगति कोई असर नहीं दिखा पाई। यही वजह है कि यहां के बच्चे भी कुपोषण के शिकार विश्व के 162 मिलियन दूसरे बच्चों की लिस्ट में शामिल हैं। इस बारे में जॉन हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक स्कूल में न्यूट्रिशन के प्रोफेसर जीन हंफ्री बताते हैं कि इन जगहों पर रहने वाले बच्चों का शरीर अपनी सारी ऊर्जा और पोषण को संक्रमण से बचाव में ही खर्च कर देता है जिसके कारण उनके मस्तिष्क के विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। जन्म के बाद के दो सालों में अगर पूरी ऊर्जा और पोषण न मिले तो बच्चा कुपोषण की ओर चला जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा चिंताजनक है बच्चे की लंबाई

**देश के पांच साल से कम 65 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनमें से एक-तिहाई बच्चे अमीर घरों के हैं। इस तथ्य के आधार पर डीन स्पीयर्स जैसे आर्थिक विश्लेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुपोषण को दूर करने में आर्थिक उन्नति नहीं बल्कि स्वच्छता की जरूरत है।**

गौर कीजिए

2011 की जनगणना के अनुसार देश के 63.3 फीसद घरों में मोबाइल की सुविधा मौजूद है।

## भारी पड़ती गंदगी

- **बच्चे पैदा करने के लिहाज से भारत सबसे खतरनाक देश है। सफाई और हवा की शुद्धता के मामले में यह सबसे खराब जगह है।**
- **भारत की आधी जनसंख्या के मुकाबले चीन में केवल एक फीसद और बांग्लादेश में केवल तीन फीसद लोग ही खुले में शौच करते हैं।**
- **भारत में मुस्लिम बच्चों के जीवित रहने की दर हिंदुओं की तुलना में 17 फीसद ज्यादा है क्योंकि वे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं।**
- **गंदे जगहों पर रहने वाले बच्चों का शरीर अपनी सारी ऊर्जा और पोषण को संक्रमण से बचाव में ही खर्च कर देता है जिसके कारण उनके मस्तिष्क के विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता।**

का कुंद हो जाना और उसका पूरा मानसिक विकास न होना। कुपोषण पर हाल में हुए अध्ययन में शोधकर्ताओं का ध्यान इस बात पर गया कि इस समस्या के मूल में भोजन की कमी होना नहीं बल्कि मानव गंदगी और मल का मिट्टी और पानी के साथ घुल कर उत्पन्न किया गया प्रदूषण है। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स में अर्थशास्त्री डीन स्पीयर्स के मुताबिक भारतीय और अफ्रीकी बच्चों की लंबाई में आया फर्क दोनों देशों के लोगों की खुले में शौच करने की आदत के बारे में बताता है। भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या अफ्रीका या दुनिया के किसी भी देश की तुलना में बहुत ज्यादा है।

कुपोषण के कारण न केवल करोड़ों बच्चों की मौत हो जाती है बल्कि जो बच जाते हैं वो न केवल कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं बल्कि अन्य बच्चों की तुलना में बेहद कमजोर और पतले भी होते हैं। कई बार ऐसे बच्चों में वयस्कों में पाई जाने वली बीमारियां जैसे डायबिटीज और हृदयरोग के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के रिसर्च और पॉलिसी उपाध्यक्ष रमनण लक्ष्मीनारायण गंदगी की भयावहता को बताते हैं कि भारत में बच्चों के कुपोषण के कारण होने वाली मानव क्षमता की क्षति अब तक के इतिहास में विश्व के किसी भी देश में होने वाली क्षति से बढ़कर है। यहां तक कि यह पूरी दुनिया में एचआईवी/एड्स से होने वाली मौतों की तुलना में केवल भारत में 20 गुना ज्यादा मौतों का कारण बनता है। भारत बच्चे पैदा करने के लिहाज से सबसे खतरनाक देश है। देश सफाई और हवा की शुद्धता में विश्व के सबसे खराब जगहों में से है।

संक्रमण और गंदगी से होने वाले रोग जैसे तपेदिक व अन्य रोग भारत में आम हैं। हर चार में से एक या ज्यादा नवजातों की मृत्यु संक्रमण से हो जाती है। दरअसल देश में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति के पीछे बहुत बड़ा कारण लोगों की मानसिकता भी है। कुछ हिन्दू ग्रंथों में यह कहा गया है कि शौच का स्थान निवास स्थान से दूर होना चाहिए। इसके निहित अर्थ को समझे बिना भारतीय घर से बाहर शौच करना जरूरी समझते हैं जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। गांधी जी ने भी लोगों के मन से इस गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की थी। 1925 में अपने एक लेख में उन्होंने लिखा था कि हमारे देश में बहुत सारी बीमारियों का कारण लोगों का जहां-तहां शौच करना या मूत्र त्याग करना है। बाहरी देशों ने अपने यहां लोगों की इस आदत को बदलने और शौचालय की व्यवस्था करने के लिए काफी कुछ काम किया है। यही वजह है कि भारत की आधी जनसंख्या के मुकाबले चीन में केवल एक फीसद और बांग्लादेश में केवल तीन फीसद लोग ही खुले में शौच करते हैं। जाहिर है कि इससे पीछे भारतीयों की मानसिकता भी है जिसे वे बदलना नहीं चाहते। इस समय देश में चल रहे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत बनाये जा रहे शौचालयों के मामले में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। लोग घर में शौच जाने के बजाय अभी भी बाहर जाना अच्छा समझते हैं। भारतीयों की इस मानसिकता से चिंतित पूर्व केंद्रीय मंत्री व अर्थशास्त्री जयराम रमेश ने कहा था कि देश में संपूर्ण सांस्कृतिक आंदोलन चलाने की जरूरत है तभी साफ-सफाई और शौचालय के प्रति लोगों की धारणा को बदला जा सकेगा।

वर्ष 2013 में मातृ एवं स्वास्थ्य पोषण पर आधारित लैनसेट सीरिज में बताया गया था कि कुपोषण को दूर करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है - राजनीतिक प्रतिबद्धता, कम लागत में अधिकतम पोषण और खाद्य सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण जैसे कारकों को सक्षम बनाना। एक नये शोध में यह बात सामने आई है कि साफ पानी में 20 फीसद और स्वच्छता में 15 फीसद के सुधार से कुपोषण को 35 फीसद तक कम करने में मदद मिली। ये ठीक है अनाज की कमी कुपोषण को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है लेकिन इसमें अब कोई शक नहीं कि सफाई अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारक है। पश्चिम के देशों में स्वच्छता का महत्व 19-20वीं शताब्दी के दौरान ही समझ लिया गया था। यही कारण है कि टीकाकरण और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बहुत पहले से ही वहां बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता गया। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद के कुछ सालों में उसे स्वच्छ माहौल मिले तो बड़े होने पर भी उसका स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। ऐसा न होने पर बीमारियों के अलावा बच्चों का कद न बढ़ने का खतरा बना रहता है। एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में मुस्लिम बच्चों के जीवित रहने की दर हिंदू बच्चों की तुलना में 17 फीसद ज्यादा होती है जबकि मुस्लिम हिंदुओं की तुलना में कम पढ़-लिखे और ज्यादा गरीब होते हैं। इसके पीछे जो कारण पाया गया वो यह था कि हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा मुसलमान शौचालय का इस्तेमाल करते हैं जबकि हिंदू अपनी परंपरा बता कर खुले में शौच करने को तरजीह देते है।

**गौर कीजिए**

**देश के केवल 46.9 फीसद घरों में ही शौचालय मौजूद है।**

# बदलते समय की मांग है राइट टू पी

मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 27 वार्डों में कामकाजी महिलाओं के लिए साफ, सुरक्षित और निःशुल्क सार्वजनिक शौचालयों की मांग लंबे अरसे से की जाती रही है। इस शहर में कामकाजी महिलाओं की चौथी पीढ़ी भी अर्थव्यवस्था में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। उनकी भूमिका निर्माण, सेवा क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयों में वेतनभोगी कर्मचारियों और अन्य प्रकार के कर्मियों के तौर पर काफी अहम मानी जाती है। इस तरह देश में मुंबई कामकाजी महिलाओं का सबसे बड़ा क्षेत्र है। वर्ष 2011 की जनगणना और एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की भागीदारी में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां काम और पढ़ाई के कारण घर से बाहर या यात्रा करते हुए समय गुजारती हैं। खासकर असंगठित कार्यक्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को तो दिन के 16-16 घंटे घर से बाहर बिताने पड़ते हैं। इन सभी महिलाओं की लगभग एक ही समस्या है-साफ और सुरक्षित शौचालय का न होना।

**प्रो. विभूति पटेल**

(पीएचडी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई तथा डायरेक्टर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूजन पॉलिसी )

## व्यवस्थित विश्राम गृह/शौचालय की मांग

ध्यान देने की बात ये है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में जल्दी-जल्दी पेशाब के लिए जाना होता है क्योंकि पुरुषों का मूत्राशय महिलाओं की तुलना में बड़ा होता है। इसके अलावा मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन बदलने के लिए अलग से विशेष कक्ष की आवश्यकता होती है। अपने कपड़ों और अन्य जरूरतों की वजह से महिलाओं को ज्यादा समय तक शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि लड़कों या मर्दों के मामले में लागू नहीं होता। लड़कों के कपड़े ज्यादा सुविधाजनक होते हैं और उन्हें मूत्र त्याग करने के लिए अधिक समय की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ-साथ महिलाओं के शौचालय को बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग शौचालय या मूत्रालय का होना एक सपने जैसा ही होता है। दफ्तरों में और सार्वजनिक स्थानों में महिलाओं के लिए अलग से साफ और सुरक्षित शौचालय का न होना महिलाओं के लिए कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा कर देता है। घर से बाहर होने पर महिलाएं ज्यादा पानी पीने से कतराती हैं जिससे कई तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। कम पानी पीने और ज्यादा देर तक पेशाब को रोके रखने की वजह से महिलाएं अक्सर पेट दर्द से परेशान रहती हैं और उनके प्रजनन अंगों में संक्रमण का डर बना रहता है। यही कारण है कि ब्लैडर इंफेक्शन भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है और बहुधा उन्हें सिस्टाइटिस का सामना भी करना पड़ता है।

## शौचालयों में लैंगिक भेदभाव

तमाम तरह की आधुनिकता और शहरीकरण के बाद भी मुंबई में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालयों की भारी कमी है। फिर चाहे वह रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे, हाईवे, औद्योगिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, पर्यटन स्थल, सार्वजनिक अस्पताल या मार्केट, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय लगभग न के बराबर होते हैं। जो कुछ महिला शौचालय हैं भी तो वे सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण बेहद गंदे और असुरक्षित हो गये हैं। ऐसे में उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हमने पाया कि महिलाओं के लिए बनाये गये ज्यादातर शौचालय जाम थे, इस्तेमाल के लायक नहीं थे, बह रहे थे या उनमें पानी नहीं था। शौचालयों में बुनियादी सुविधाओं के न होने के कारण महिलाएं अक्सर या तो शौच के लिए जाती ही नहीं या अगर जाती भी हैं तो उन्हें अपने सम्मान के साथ

## बीएमसी के मुताबिक 2013 में मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहा

| *LADIES* | | | GENTS | | | HANDICAPPED | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *URINALS* | *WC* | *BATHROOM* | URINALS | WC | BATHROOM | URINALS | WC | BATHROOM |
| *113* | *5136* | *61* | 3705 | 8305 | 191 | 0 | 15 | |

समझौता करना पड़ता है। यही कारण है कि 18 महीने पहले मुंबई में शूरू किया गया राइट टू पी कैंपेन 'पॉटी पैरिटी' की मांग करता है। राइट टू पी अभियान मुंबई के 40 स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शुरू किया गया है जो पैसे देकर इस्तेमाल करने वाले शौचालयों में महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है। शहर में निजी कंपनियों द्वारा संचालित ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय केवल पुरुषों को पैसे देकर शौचालय का इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं जबकि महिलाओं और लड़कियों के लिए यह सुविधा मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं जहां महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध है वहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग चार्ज किया जाता है। मध्य और पश्चिमी रेलवे में सफर करने वालीं और वहां काम करने वाली महिलाएं अक्सर ये शिकायत करती हैं कि स्टेशनों पर मौजूद शौचालयों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अटेंडेंट अक्सर पुरुषों को बिना पैसे के शौचालय में जाने देते हैं जबकि उनसे दो रुपये ले लिये जाते हैं। अधिकारिक तौर पर इस समय मध्य रेलवे के तहत पड़ने वाले इन स्टेशनों पर पे एंड यूज शौचालय हैं-सीएसटी, मस्जिद, संधुसर्त रोड, करी रोड, परेल, घाटकोपर, कुर्ला, बाइकुला, एलटीटी, भंडुप, करजात, डोम्बीवली, कल्याण, मुंब्रा, नाहुर, सेवरी, पनवेल, वडाला और लोनावाला जबकि पश्चिमी रेलवे के तहत जो स्टेशन आते हैं वे ये हैं -चर्चगेट, मरीन लाइंस, ग्रांट रोड, मुंबई सेंट्रल, चर्नी रोड, महालक्ष्मी और एलफिन्सटन रोड।

## राइट टू पी अभियान की मुख्य मांगें

- महिलाओं के लिए अलग निःशुल्क और सुरक्षित सार्वजनिक मूत्रालय बनाए जाएं
- लाचार महिलाओं के लिए विशेष सुविधा हो
- शौचालयों के मुख्य द्वार पर उसके निःशुल्क होने की सूचना चिपकाई जाय
- महिला शौचालयों में प्रदत्त सुविधाओं की देख-रेख महिला संगठनों अथवा महिला कर्मचारियों द्वारा ही कराई जाय
- शौचालयों में कूड़ेदान और सेनेटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध हो
- हर दो किलोमीटर के दायरे में एक महिला शौचालय का निर्माण कराया जाय
- महिलाओं के लिए बनाये गये शौचालयों व मूत्रालयों का प्रबंधन महिलाओं के लिये काम करने वाले संगठनों को दिया जाय जबकि उसकी वित्तीय जिम्मेदारी बीएमसी के पास रहे
-महिला शौचालयों की शुरुआत पहले प्रायोगिक तौर पर होनी चाहिए और उसके बाद इसे प्लानिंग में शामिल किया जाय

## परेशान करने वाली सच्चाई

मुंबई में चल रहे अभियान के तहत स्वैच्छिक संगठनों ने 129 शौचालयों का सर्वे किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, कार्यशालाएं आयोजित कीं, विशेषज्ञों के साथ इस मुद्दे पर विमर्श किया और पचास हजार हस्ताक्षरों के साथ विश्लेषणात्मक सर्वे रिपोर्ट को बीएसमी को सौंपा। आरटीई के तहत मिली सूचना के मुताबिक मुंबई के 24 वार्डों में कुल 6568 मूत्रालय पुरुषों के लिए बनाये गये हैं। दूसरी ओर, 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई में महिलाओं की कुल संख्या 741632 है जबकि उनके लिए एक भी मूत्रालय नहीं है।

## लैंगिक प्रतिबद्धता को बजट में सामने लाना

महाराष्ट्र में 8 मार्च 2013 को जारी महिला नीति के मुताबिक राज्य में हर बीस किलोमीटर पर एक महिला शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए। राइट टू पी अभियान मुंबई में हर एक किलोमीटर पर एक महिला शौचालय की मांग करता है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम के वर्ष 2013-14 के बजट में महिला शौचालयों के निर्माण के लिए भी बजटीय राशि का आवंटन किया गया है। इसमें कहा गया है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं के लिए पृथक शौचालयों का निर्माण कराया जाना चाहिए। हालांकि नगर निगम ने 25 शौचालयों के निर्माण के लिए महज 75 लाख रुपये का आवंटन किया है जो बहुत कम है। साथ ही अभी तक शौचालयों के निर्माण का काम भी शुरू नहीं किया गया है।

**गौर कीजिए**

**झारखंड के सबसे ज्यादा 77 फीसद घरों में शौचालय मौजूद नहीं है।**

## नगर निगम के जेंडर बजट की आलोचना

नगर निगम के बजट में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने के लिए जिन कारणों को सामने रखा गया है वह उसकी पुरुषवादी सोच को दर्शाता है। इसमें शौचालयों का निर्माण उन स्लम इलाकों में करवाने की बात कही गई है जहां शौचालय नहीं है। साथ ही इस योजना को खुले में शौच मुक्त महाराष्ट्र स्कीम के अंतर्गत रखा गया है। इससे ऐसा लगता है कि बजट में महिलाओं को केवल घरेलू के तौर पर रखा गया जबकि कामकाजी महिलाओं की जरूरत को नजरअंदाज कर दिया गया। भीड़-भाड़ वाली जगहों में शौचालय बनवाने की योजना को भी ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। 25 शौचालयों के लिए जो 75 लाख रुपये आवंटित किये गये थे उनका भी इस्तेमाल नहीं हुआ और अब तक शौचालयों का निर्माण शुरू नहीं कराया गया। इतना ही नहीं राइट टू पी के कार्यकर्ताओं द्वारा शौचालय निर्माण के लिए जो जगहें बताई गई थीं उन्हें भी निजी जमीन, रेलवे की जमीन, बिल्डरों और रोड डीपो जैसी जमीनें बताकर खारिज कर दिया गया। नगर निगम के बजट में महिला शौचालयों के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था गरीबों की झोपड़ियों को गिराकर कराने की बात कही गई है जो अमानवीय और गरीब विरोधी है और उसका विरोध किया जाना चाहिए।

## वक्त की जरूरत

एमसीजीएम को सबसे पहले लैंगिक भेदभाव मिटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी होगी फिर उसके बाद ही वित्तीय प्रतिबद्धताओं के जरिये परिणाम को सामने आने का मौका मिलेगा। मुंबई में महिला शौचालय हर महिला की जरूरत है। कॉलेज और ऑफिस जाने वाली लड़कियां लंबी दूरी की यात्राएं करती हैं तो इसके लिए रेलवे स्टेशनों और बस डीपो में सुचारू और इस्तेमाल योग्य शौचालय होने चाहिए। घरेलू महिलाओं को बाजार जाना पड़ता है, पार्क और अस्पताल जैसी जगहों पर उनके लिए भी शौचालय होने चाहिए। चाहे स्लम इलाका हो या नहीं, महिलाओं को भी पुरुषों की तरह हर जगह शौचालय की जरूरत होती है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी शौचालयों में महिलाओं के लिए ब्लॉक होने चाहिए जिसकी देख-रेख महिलाओं के हाथ में रहे। बजट में महिला शौचालयों के लिए कुल 89.1 करोड़ रुपये के वित्तीय अनुदान की जरूरत है। इसका गणित इस प्रकार से लगाया जा सकता है-सभी 27 वार्डों में 100 शौचालयों के हिसाब से कुल 2700 शौचालयों का निर्माण कराना होगा और एक शौचालय के निर्माण में 3 लाख का खर्च आएगा तो इस हिसाब से सभी शौचालयों को बनाने में 81 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इसी तरह हर ब्लॉक में कर्मचारियों के वेतन, बिजली, कचरा पेटी, सफाई और पानी की व्यवस्था पर कुल 30,000 रुपये का खर्च आएगा जो सभी 2700 ब्लॉकों को मिलाकर 8.1 करोड़ हो जाएगा। देखा जाय तो नगर निगम के पूरे बजट के आकार की तुलना में यह राशि बहुत ज्यादा नहीं है। 27578.67 करोड़ के बजट के सामने महज 89.1 करोड़ महिला शौचालयों के लिए देना बहुत मुश्किल नहीं है। बीएमसी ने अपने बजट में जेंडर बजट को स्थान देना वर्ष 2009-10 से शुरू किया था। इस साल स्वच्छता के लिए कुल 514 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राइट टू पी कैंपेन चाहता है कि कुल बजट का केवल 0.0032 फीसद और स्वच्छता बजट का 16.5 फीसद आवंटन महिला शौचालयों के लिए किया जाय। वैसे भी वुमेन काम्पोनेंट प्लान के तहत यह कहा गया है कि हर विकास राशि का 30 फीसद महिलाओं के विकास के काम में लगाया जाना चाहिए।

मुंबई में किया गया यह अध्ययन इस उद्देश्य को सामने रखता है कि देश के हर शहर में लोग महिलाओं के लिए विश्राम गृहों और शौचालयों के निर्माण के लिए अभियान चलाएं क्योंकि पूरे देश में ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है जो 16-16 घंटे तक घर से बाहर सफर करती हैं। भारत जैसे देश में जहां की महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान देती हैं, महिलाओं के शौचालय और मूत्रालय जाने के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।

**गौर कीजिए**

**पूरी दुनिया में 780 मिलियन लोग साफ पानी से वंचित हैं।**

आंखों देखी

# हर हाथ में मोबाइल का फायदा क्या ?

डा. मीरा मिश्रा

(समाज सेविका एवं लेखिका )

पिछले दिनों मुझे बिहार में हाजीपुर जिले के एक गांव के प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र को देखने का मौका मिला। वह चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरे एक टूटे-फूटे दो कमरों के मकान में चलाया जा रहा था जिसकी बदरंग दीवालों के ऊपर मकड़ियों के जाल का अंबार फैला हुआ था। मुझे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि वहां न तो नल या चापाकल था न ही कोई शौचालय। कमरे के पिछवाड़े के झुरमुट को औरतें शौचालय और कूड़ाघर के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं। उपकेन्द्र संभालने वाली महिला कर्मचारी भी पेशाब करने पिछवाड़े जाती थी। उपकेन्द्र का बायोमेडिकल कचरा जिसमें खून मवाद से सनी रुई एवं टूटी सुइयाँ, पुरानी दवाइयाँ, प्लास्टिक सब कुछ एक साथ पिछवाड़े की खुली जमीन में आधा अधूरा गाड़ दिया जाता है। उसी कूड़े कचरे के ढेर के बीच महिलाएं टायलेट जाने के लिए मजबूर थीं। शाम को गांव से लौटते समय सड़क के दोनों ओर हाथ में लोटा लिए एक-दूसरे से बातें करती महिलाओं का झुंड दिखा। कुछ महिलाएं गाड़ी की रोशनी की परवाह किए बगैर किनारों पर बैठी रही और एक-दूसरे से बातें करती रहीं। मेरे पास बैठी गांव की महिला ने बताया कि पहले जब सड़क नहीं थी और आसपास के खेतों में इतने मकान नहीं बने थे तब झाड़ीदार पौधे मसलन अरहर गन्ना इत्यादि में दिन के उजाले में भी महिलाएं व बच्चियां शौच के लिए चली जाती थीं परंतु प्रायः गांव की महिलाओं को रात का अंधेरा होने तक इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसके अनुसार अब गांव के कई घरों में शौचालय बन गया है परंतु अधिकांश घरों में शौचालय का इस्तेमाल लड़कियां और नयी नवेली बहुएं ही करती हैं। शौचालय जल्दी भर न जाए इसलिए भी लोग उसका कम से कम इस्तेमाल करते हैं। उम्र दराज स्त्रियां एवं घर के पुरुष अब भी खुले में ही शौच करना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर वे दिन भर के काम की थकान के बाद आपस में इसी बहाने एक-दूसरे से मिलकर गपशप करते हुए हवाखोरी भी कर लेते हैं। मेरे पूछने पर कि दिन में शौच आने पर महिलाएं क्या करती हैं, उसने बताया कि वे उन गली कूचों का इस्तेमाल करती हैं जहां आमतौर पर लोग कूड़ा फेंकते हैं। कई घरों में औरतें मिट्टी की हंडिया या प्लास्टिक की थैलियों को भी प्रयोग में लाती हैं। वैसे अमूमन तो वो कोशिश करती हैं कि कम खाएं या ऐसा कुछ नहीं खाएं कि बेवक्त बाहर जाना पड़े। बरसात होने पर महिलाओं को बहुत परेशानी होती है।

अगले दिन हमें दूसरे गांव के प्राइमरी स्कूल में जाना था जो सड़क से काफी दूर था। एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम एक बगीचे में पहुंचे जिसके तीन ओर केले के खेत थे। स्कूल की दशा भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र जितनी ही खराब थी। चार पांच बच्चों से घिरीं एक शिक्षिका बैठी थीं जिनसे पूछने पर पता चला वहां भी टायलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर का चापाकल भी टूटा हुआ था इसलिए बच्चे बगल के मकान के अहाते में लगे चापाकल से पानी पीते थे। शौचालय के लिए केले के खेतों में प्राइवेसी मिल जाती थी इसलिए काम चल जाता था। बच्चों की उपस्थिति खिचड़ी बांटते समय बढ़ जाती थी। वहाँ से दो किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव था जो मुख्य सड़क से आधा किलोमीटर की दूरी पर था। वहां सरकारी मिडिल स्कूल था जिसमें लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। यहां स्कूल के जर्जर भवन से दूर स्कूल के अहाते के कोने में बांस और बोरे से घेरकर लड़कियों के लिए पेशाबघर की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी। शौचालय की यहां भी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं थी। किशोर वय की लड़कियां मासिक के दौरान स्कूल से अनुपस्थित रहती थीं। टायलेट के पास डस्टबिन के नाम पर कुछ भी नहीं था इसलिए कोने में कूड़े के ढेर में लड़कियां खुले में सैनिटरी नैपकिन जो फटे पुराने गंदे कपड़ों चिथड़ों के

**गौर कीजिए**

**विकासशील देशों में एक व्यक्ति पूरे दिन में जितने पानी का इस्तेमाल करता है उतना एक अमेरिकी पांच मिनट नहाने में खर्च कर देता है।**

टुकड़े थे, फेंकती थीं। अगल बगल लैटरिन फैली हुई थी जिसके बीच आना लड़कियों की मजबूरी थी। जिन्हें गंदगी से परहेज था वो टट्टी पेशाब रोक लेती थी और घर जाकर ही निवृत होती थीं। गांव की अधिकांश लड़कियां मासिक शुरू होते ही पढ़ाई छोड़ देती थीं क्योंकि स्कूल में परेशानी होती थी। गांव में महिला मुखिया के घर हमें कुछ जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए रुकना था। उनके घर के अन्दर शौचालय की व्यवस्था थी परंतु वह सीढ़ी के नीचे छोटी सी अंधेरी सीलनभरी जगह में बना हुआ था। पाट की गंदगी एवं टूटी फूटी बाल्टी में छलकते गंदे पानी को देखकर हम समझ गये थे कि शौचालय एवं साफ सफाई यहां के लोगों के लिए उपेक्षित विषय है जिसपर किसी का ध्यान नहीं जाता।

गांव से पटना आते समय हमें रास्ते में कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं दिखा। रास्ते में बने ढाबों पर नाश्ता करने के बहाने रुककर महिलाएं वहां बने उपेक्षित गंदे शौचालयों का मजबूरी में प्रयोग करती हैं।

अपनी शारीरिक बनावट एवं लोक लाज के कारण वो खुले में सार्वजनिक रूप से पेशाब नहीं कर सकती हैं। शहर के अन्दर भी पर्याप्त सुलभ शौचालय नहीं बने हैं। जो बने हैं उसमें गरीब लोग नहीं जाते क्योंकि जानेपर पैसा लगता है। बस अड्डा अथवा अन्य कुछ स्थानों पर जो सार्वजनिक शौचालय बने हैं वो टूटे फूटे भीषण गंदगी एवं बदबू के कारण अनुपयोगी हैं। शौचालय की खराब क्वालिटी एवं रखरखाव की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से ये कुछ दिनों बाद बेकार हो जाते हैं। पटना में शाम के समय चितकोहरा पुल के पास से गुजरते समय मैंने देखा कुछ महिलाएं और बच्चियां सड़क के किनारे शौच के लिए बैठी हुई थीं और दूर खड़े कुछ शोहदे उनपर छींटाकशी कर रहे थे। कुछ अन्य महिलाएं नाली पर रखा हुआ स्लैब उठाकर नाली को शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रही थीं। एक लड़की तो बैठकर मोबाइल पर आराम से बातें भी कर रही थी। मैंने एक महिला को रोककर ऐसा करने से मना किया। उसने बताया कि स्लम बस्ती में सरकार ने जो शौचालय बनवाया था वह अब परिवार बढ़ने के बाद सबके लिए कम पड़ रहा है। उसकी दीवार ढह रही है और नल में पानी भी नहीं आता। दरवाजा टूटा होने से महिलाओं को दिक्कत होती है क्योंकि उनके लिए अलग व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बस्ती के लोग साफ सफाई में टालमटोल करते हैं जिसके कारण वहाँ बहुत गंदगी रहती है। नल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने से बाहर गंदे पानी के नीचे पाइप तोड़कर प्लास्टिक के पाइप से पानी निकालते हैं जो पीने के काम में भी लाते हैं।

उपर्युक्त तस्वीरों से हम सैनिटेशन की वर्तमान हकीकत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। सैनिटेशन हमारे लिए हमेशा से ही एक उपेक्षित विषय रहा है। इसमें भी महिलाओं के लिए इसकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए इस पर गंभीरता से कोई विचार नहीं करता। घर समाज में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय महिलाओं को आज भी शरीक नहीं किया जाता जिससे घर बनाते समय उनकी सुविधा एवं हाइजिन के अनुरूप घर में टायलेट कहाँ और कैसा बनना चाहिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता। भारत के अधिकांश गांवों में खुले में शौच करना एक परंपरागत तरीका है जो लोगों की आदत का एक हिस्सा भी है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं कृषि योग्य घटती जमीन, गांव से शहरों की ओर पलायन करती बड़ी आबादी, सिमटते वन, चरागाह, खुली जमीन तथा पसरते कंक्रीट के जंगल अब पुराने समय से चली आ रही खुले में शौच करने की परंपरा को कायम रखने के लिए मुफीद नहीं हैं। आजादी के बाद देश ने विकास के कई आयाम देखे। सूचना तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में क्रान्तिकारी बदलाव आया परंतु प्रत्येक व्यक्ति और खासकर महिलाओं के लिए आज तक स्वच्छ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को किसी सरकार ने गंभीरता से लिया ही नहीं। महिलाओं को शौच के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है जिससे बचने के लिए वो दिन भर कई जतन करती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होता है। इसके लिए वो अक्सर रेशेदार कम भोजन करेंगी या पानी कम पियेंगी जिससे शारीरिक रूप से कमजोर एवं कुपोषण का शिकार हो जायेंगी। खुले में शौच हैजा डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करता है। महिलाओं को मासिक के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है जो बच्चेदानी के कैंसर का मुख्य कारण बनता है। खुले में शौच महिलाओं बच्चियों से होने वाले छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण एवं हिंसा को बढ़ावा देता है जिसके बारे में हम आये दिन खबरों में देखते सुनते रहते हैं। सुनसान जगह पर सांपों तथा अन्य जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है जो जानलेवा होता है। महिला सशक्तिकरण के लिए किये जा रहे सभी प्रयास ऐसे में बेमानी हो जाते हैं क्योंकि इसके अभाव में न जाने कितनी लड़कियां चाहते हुए भी स्कूल नहीं जा पातीं। विश्व फलक पर अगर देखा जाए तो गरीब एवं विकासशील देशों की अधिकांश महिलाएं आज भी इस समस्या से जूझ रही हैं। महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय एवं पेयजल को उनके जीवन के अधिकार क्षेत्र में लाने की पहल 2010 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में चल रही बहस के दौरान की गयी थी। उसके बाद विश्व के कई देशों ने इस दिशा में सुधार के लिए अपने देश में कई

आंखों देखी

योजनाएं चलायीं। हमारे देश में आज भी 48 प्रतिशत आबादी तमाम प्रयासों के बावजूद सैनिटेशन की सुविधा से महरूम है जबकि बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने अपनी बहुत बड़ी आबादी को यह सुविधा उपलब्ध कराकर खुले में शौच जानेवालों की संख्या को काफी कम कर दिया है। दुनिया भर में किये गये सर्वेक्षणों में यह देखा गया कि विश्व की 2.5 बिलियन आबादी के पास पुख्ता सैनिटेशन उपलब्ध नहीं है। इसमें 1.1 बिलियन लोग आज भी खुले में शौच करने के लिए विवश हैं जिसमें 636 मिलियन लोग सिर्फ हमारे देश से आते हैं। महिलाएं शौच के लिए उपयुक्त स्थान ढूँढ़ने में नित्य 300 मीटर पैदल चलती हैं तथा अपनी कार्यावधि का बड़ा हिस्सा इसमें गंवाती हैं। अंधेरे में सुनसान रास्तों पर कई बार महिलाएं अपहरण बलात्कार एवं हत्या की शिकार हो जाती हैं। पिछले साल बदायूं जिले की दो बहनों को शौच के लिए बाहर जाते समय अगवा कर लिया गया था और दरिन्दों ने उनका बलात्कार करने के बाद हत्या कर पेड़ पर लटका दिया था। इस घटना ने इस समस्या पर पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। गांवों में हैजा एवं डायरिया जैसी महामारियों की सबसे बड़ी वजह भी यही है जिससे हर साल कितने बच्चों एवं बड़ों की मौत होती है।

वर्तमान विकास की प्रक्रिया का एक कड़वा सच यह भी है कि मनुष्य की बुनियादी जरूरतों तक सबकी समान रूप से पहुंच नहीं है जिसके कारण हाशिये पर खिसकता समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मानवाधिकार के अंतर्गत तय किए गये बुनियादी अधिकारों से भी वंचित है। सबको स्वच्छ पेयजल, शौचालय, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा सिर के ऊपर छत उपलब्ध कराना सरकार की जवाबदेही है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर अनगिनत योजनाएं चल रही हैं परंतु उनके लिए बाहर सार्वजनिक स्थानों रेल, बस स्कूल, अस्पताल सड़कों के किनारे अलग महिला शौचालय जैसी जरूरी सुविधा पर किसी ने गंभीरता से विचार कर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत ही महसूस नहीं की। मोदी सरकार ने इसे अपने एजेंडे में लिया है परंतु इससे जुड़ी अधिकांश योजनाओं पर राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी होती है जो अपने ढंग से कार्य करती हैं। सरकारी शौचालयों की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। बिहार में भूमिहीनों की बड़ी संख्या सरकारी जमीनों पर, रेलवे लाइन के करीब, गंदे नालों के किनारे अथवा सड़कों पर बसी हुई है जो अक्सर अपना स्थान बदलते रहते है। इनकी महिलाओं के पास खुले में शौच के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मजदूर औरतें जो ईंट भट्ठा, कन्स्ट्रक्शन जैसे कार्यो से जुड़ी होती हैं उनके पास भी कोई व्यवस्था नहीं होती। कई जगह सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों में भी पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं होते।महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण की कुछ योजनाएं पहले से चल रही थी जो नाकाफी थीं। मोदी सरकार द्वारा इसे प्राथमिकता दिए जाने से स्थिति सुधरने की संभावना बढ़ गयी है। सबसे पहले यह देखना चाहिए वो कौन सी औरतें है जो खुले में शौच करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें चिन्हित कर उनके लिए शौचालय निर्माण को प्राथमिकता देना चाहिए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण एवम् उसकी आवश्यकता से जनता को जागरूक करने के लिए कैम्पेन चलाया जाना चाहिए। निजी शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आसान व्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, सस्टेनेबल ईकोफ्रैंडली शौचालयों के बारे में जानकारी एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, यह भी एक तरीका है। सार्वजनिक स्थलों पर पुरुष एवं महिला शौचालय दोनो अलग बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण से जुड़ी सभी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं साफ सफाई से जुड़े अभियानों को स्कूल कॉलेजों, झुग्गी झोपड़ियों, स्लम बस्तियों, मजदूरों के रिहाइशी बसेरों, गांवों कस्बों सभी जगह की महिलाओं व बच्चों के बीच ले जाना चाहिए। जरा सोचिए हर घर में शौचालय हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, साफ सुथरा माहौल हो, महिलाओं में असुरक्षा का भय नहीं हो तब सही मायने में समाज विकसित होगा और हर हाथ में मोबाइल की उपयोगिता सार्थक होगी।

**गौर कीजिए**

**वर्ल्ड बैंक ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी होती है उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है।**

अध्ययन

# अच्छी सेहत की गारंटी नहीं है स्वच्छता अभियान

देश में स्वच्छता को लेकर जो अभियान नरेंद्र मोदी ने छेड़ा है, वह काबिल-ए-तारीफ है। सफाई के प्रति भारतीयों के मन में ललक पैदा करने की इस मुहिम का देश और समाज पर व्यापक असर होगा लेकिन सच्चाई ये है कि केवल स्वच्छता अभियान चला लेने से ही स्वास्थ्य के गिरते स्तर को उठाना संभव नहीं होगा। देश के सौ गांवों में, जहां शौचालयों का निर्माण कराया गया है, कराये गये अध्ययन में पाया गया कि अच्छी सेहत के लिए इससे बढ़कर भी बहुत कुछ करना होगा। लैन्सेट ग्लोबल हेल्थ द्वारा कराये गये इस अध्ययन में पाया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वच्छता मुहिम के तौर पर जाना जाने वाला भारत का संपूर्ण स्वच्छता अभियान जिसके तहत देश भर में 25 हजार से ज्यादा घरों में शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है, मानव मल से उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने में कामयाबी नहीं पा सका है। गंदगी से होने वाली बीमारियों डायरिया, संक्रमण और बच्चों में कुपोषण के मामले कम नहीं हुए हैं।

## लैन्सेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट

दुनिया भर में करीब 2.5 बिलियन लोग शौचालय की सुविधा से विहीन हैं और इनमें से एक-तिहाई भारत में रहते हैं। इसी तरह खुले में शौच करने वाले 1.1 बिलियन लोगों में से दो-तिहाई और गंदगी से होने वाले डायरिया से हर साल मरने वाले 1.5 मिलियन लोगों में से एक-तिहाई लोग भी भारत में रहते है। यह अध्ययन उड़ीसा के 100 गांवों के 9480 घरों में रहने वाले 50951 लोगों पर कराया गया था। इनमें से चार साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया था। अध्ययन के दौरान वर्ष 2011 की शुरुआत में 50 गांवों को चुन कर वहां स्वच्छता मामले में हस्तक्षेप बढ़ाया गया जबकि 50 अन्य गांवों में 14 महीने की निगरानी के बाद सफाई के मामले में दखलअंदाजी की गई। पाया गया कि जिन गांवों में दखल बढ़ाई गई थी वहां के घरों में शौचालय का आंकड़ा 9 फीसद से बढ़कर 63 फीसद हो गया जबकि 14 महीने तक निगरानी में रखे गये गांवों में यह संख्या 8 फीसद से बढ़कर 12 फीसद तक ही हो पाई थी। हालांकि जिन गांवों में शौचालयों की संख्या बढ़ी थी उनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के मामले कम नहीं हुए। यानी खुले में शौच के मामले कम होने का असर डायरिया जैसी गंदगी से होने वाली बीमारियों पर नहीं देखा गया। हस्तक्षेप वाले गांवों में सात दिन में सामने आने वाले डायरिया के मामले 8.8 फीसद रहे जबकि बिना हस्तक्षेप वाले गांवों में यह आंकड़ा 9.1 फीसद रहा। इसके अलावे सफाई के लिए होने वाला दखल मिट्टी के जरिये प्रवेश करने वाले परजीवी कीटाणुओं के खतरे को भी कम नहीं कर सका। ये कीटाणु शारीरिक विकास को अवरुद्ध करते हैं और उनकी क्रियाशीलता को संज्ञानात्मक स्तर तक कम कर देते हैं। सफाई का बच्चों के पोषण स्तर, वजन या लंबाई पर भी कोई असर नहीं देखा गया।

अध्ययन के प्रमुख रहे प्रोफेसर थॉमस क्लासेन (एमोरी विश्वविद्यालय, अटलांटा व लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसीन) के मुताबिक स्वच्छता कार्यक्रम शौचालयों का निर्माण कराने में प्रभावशाली है मगर इसमें भी सभी लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, लोग हमेशा शौचालय का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। खराब हाइजीन और दूषित पानी, बच्चों के मल और लोगों की प्रवृत्ति, इन सबके मिलने से जो नतीजा निकलता है वह सेहत पर भारी पड़ता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस बात पर अध्ययन होने चाहिए कि आखिर क्यों स्वच्छता अभियानों के बाद भी बीमारियों पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखने को कहा कि शौचालयों का इस्तेमाल न करना, मल को ढंकने की व्यवस्था न होना और जानवरों के मल का प्रबंधन न होने जैसे कारक रोगों के पैदा होने में सहायक होते हैं। स्टैन्फोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ के रिसर्च डिप्टी डायरेक्टर डा. स्टीफन लूबी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निराशाजनक नतीजों को पाने से बेहतर है कि कार्यक्रमों का कठोर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

**गौर कीजिए**

**साबुन से हाथ धो लेने भर से डायरिया का खतरा चालीस फीसद कम हो जाता है।**

रियल हीरो

# संकोच की चुप्पी तोड़ने की हिम्मत

**प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर लोगों को साफ रहने और साफ करने का संदेश दिया है। उनकी इस पहल की देश-दुनिया में जमकर तारीफ हो रही है। ये ठीक है कि देश में ऐसे राजनेताओं के नाम गिनती में रहे हैं जिन्होंने सफाई को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई हो लेकिन ऐसे आम लोगों की कमी नहीं रही जिनकी कोशिशों से कई गांवों और पंचायतों को नई पहचान मिली। कहीं संगठन के रूप में तो कहीं अकेले ही इन लोगों ने संकोच की चुप्पी तोड़ने की हिम्मत दिखाई है।**

## विश्व शौचालय संगठन — जैक सिम

वर्ष 2001 में चीन के जैक सिम ने दुनिया को वर्ल्ड ट्यालेट आर्गेनाइजेशन से रू-ब-रू कराया। एक संगठन जो शौचालय की बात करता है, लोगों की शौच जाने की आदतों को परखता है और शौचालय न होने के दुष्परिणामों से दुनिया को अवगत कराता है। एक सफल बिजनेसमैन जैक सिम ने 40 की उम्र में अपने व्यवसाय से खुद को अलग कर लिया। अपने जीवन की दिशा को बदलने की चाहत में सिम ने कई यात्राएं कीं। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारों के लिए न बोल पाने वाले लोगों की जमात देखी जो अपने स्वास्थ्य, मर्यादा और जिंदगी के साथ समझौता कर रहे थे। जैक ने देखा कि लोगों की दिनचर्या में शौचालय का सबसे अहम स्थान होने के बाद भी लोग उसकी अनदेखी करते हैं और उसके बारे में बात करना शर्मनाक समझते हैं। यही वजह है कि विश्रामगृहों के बारे में भी ज्यादातर देशों में नहीं सोचा जाता। 1998 में जैक ने रेस्टरूम एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर की स्थापना की जो सिंगापुर के साथ-साथ पूरे विश्व में सार्वजनिक शौचालयों के मानकों के बारे में बात करता था। अपने एसोसिएशन के जरिये जैक शीघ्र ही सिंगापुर के साथ-साथ दुनिया भर के देशों में जाने जाने लगे। जैक को पता लगा कि अन्य देशों में भी शौचालय की बात करने वाले संगठन हैं लेकिन उन्हें एक साथ लाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। जानकारियों को साझा करना और संसाधनों व अन्य उपायों के आदान-प्रदान का कोई जरिया न होने के कारण संगठनों को साथ लाना मुश्किल था। इन बाधाओं को दूर करने के लिए जैक सिम ने वर्ष 2001 में वर्ल्ड ट्यालेट आर्गेनाइजेशन का गठन किया और चार साल बाद वर्ष 2005 में वर्ल्ड ट्यालेट कॉलेज की स्थापना की। आज 58 देशों के 235 संगठन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत काम कर रहे हैं। 19 नवम्बर, 2001 को अपने स्थापना दिवस को डब्ल्यूटीओ ने विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी मान्यता दे दी।

आज पूरी दुनिया इस दिन को शौचालयों के विकास और स्वच्छता के दिवस के तौर पर मनाती है। अपने कामों की वजह से जैक जल्दी ही लोकप्रिय हो गये और उन्हें सिंगापुर सहित अन्य देशों द्वारा सम्मानिक किया जाने लगा। 2007 में वे स्वच्छता के लिए काम कर रहे विश्व के 130 संगठनों के गठबंधन सस्टेनेशबल सैनिटेशन एलायंस (सुसानए) के सबसे प्रमुख सदस्य बन गये। अशोका ग्लोबल फेलो रह चुके जैक को 2008 में टाइम मैगजीन ने पर्यावरण के हीरो का नाम दिया।

## सुलभ शौचालय — बिंदेश्वर पाठक

भारत में शौचालय के महत्व को बताने और विस्तार के पीछे सुलभ इंटरनेशनल का नाम प्रमुखता से आता है। सुलभ के अभियान को आगे बढ़ाने में तकनीकी का भी बड़ा हाथ है। 70 के दशक में जब खुले में शौच की आदत ने देश को परेशान कर रखा था तब सुलभ ने अपने टू-पिट और पोर फ्लश शौचालय के जरिये गांव-देहातों तक अपनी पैठ बना ली। यह तकनीक शौचालय के लिए सस्ती, सुलभ और सुविधाजनक थी। डा. पाठक का शौचालय अभियान तत्कालीन केंद्र सरकार की मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने की योजना को सफल बनाने में बहुत काम आया। सुलभ इंटरनेशनल ने देश भर में पैसे देकर इस्तेमाल करने वाले शौचालय का निर्माण कर सार्वजनिक शौचालयों की दिशा में क्रांति ला दी। बाद में इसने कचरे और मानव मल से बायोगैस के निर्माण के लिए भी काम किया। सुलभ ने 7500 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जिनमें नहाने, कपड़े धोने और पेशाब करने की भी व्यवस्था है। वर्तमान में सुलभ 27 राज्यों और पांच केंद्र शासित राज्यों में अपने पचास हजार प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों

**गौर कीजिए**

**विश्व के कुल अनाज उत्पादन में आधा योगदान महिलाओं का होता है।**

रियल हीरो

के साथ काम कर रहा है। पटना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में ग्रेजुएट बिंदेश्वर पाठक एक निपुण वक्ता और लेखक भी हैं। उनकी लिखित 'द रोड टू फ्रीडम' ने अच्छी लोकप्रियता पायी। वर्ष 1968 में मैला ढोने वालों का दर्द नजदीक से देखने के बाद श्री पाठक ने जाना कि देश में शौचालयों की जरूरत कितनी ज्यादा है। इसी साल वे बिहार गांधी सेन्टेनरी सेलिब्रेशन कमेटी के भंगी मुक्ति सेल से जुड़े और इसके तहत उन्हें देश भर की भंगी बस्तियों में रहने का मौका मिला। इस दौरान वे अपना पीएच-डी भी करते रहे। अपनी यात्राओं के दौरान ही उन्होंने ठान लिया था कि मैला ढोने वालों को मुक्ति दिलाने के लिए वे जरूर कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि यह कुप्रथा आने वाले समय में देश को विनाश की ओर ले जाएगी। 1970 में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की जिसमें मानवीय पहलुओं को ध्यान रखते हुए नई तकनीकों की खोज और इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई। यह संगठन अपने पचास हजार स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के साथ मिलकर देश भर में सार्वजनिक शौचालयों का संचालन कर रहा है। कचरा प्रबंधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का इस्तेमाल करना भी संगठन के उद्देश्यों में शामिल रहा है और इसमें यह काफी हद तक सफल भी रहा है। अपने स्वच्छता अभियान के तहत श्री पाठक ने न केवल लाखों लोगों तक शौचालयों को पहुंचाया है वहीं दुर्गंध रहित बायोगैस के निर्माण और फास्फोरस व अन्य खनिजों से युक्त पेयजल उत्पादन की दिशा में भी काम किया है।

अपने विशिष्ट कार्यों के लिए बिंदेश्वर पाठक को देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2003 में उनका नाम ग्लोबल 500 में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा उन्हें एनर्जी ग्लोब अवार्ड, द दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज और फ्रांस के लीजेंड ऑफ प्लैनेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जनवरी, 2011 में श्री पाठक को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में लेक्चर के लिए भी आमंत्रित किया गया था।

## जोडी अंडरहिल — माउंटेन क्लीनर्स

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों और सड़कों पर से कचरा उठाती युवाओं की एक टीम अक्सर दिख जाती है। टीम का नेतृत्व करती जोडी अंडरहिल को तो लोग अब गारबेज गर्ल यानी कचरा गर्ल के नाम से भी पुकारने लगे हैं। बकौल जोडी, तिब्बति बच्चों के लिये काम करने वे भारत आई थीं और मैकलॉयडगंज में रुकी थीं लेकिन एक बार जब वे बाकशु आईं तो यहीं की होकर रह गईं। इस खूबसूरत जगह पर तीर्थयात्रियों और सैलानियों द्वारा फैलाये गये कचरे को देखकर जोडी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़कर पूरे इलाके की सफाई करने का काम शुरू कर दिया। यहीं से माउंटेन क्लीनर्स का जन्म हुआ। अपने अभियान के तहत वे न केवल गंदगी और कचरे को साफ करती हैं बल्कि लोगों को और खासकर बच्चों को सफाई के बारे में बताती भी हैं। कचरों का सही प्रबंधन, पानी, स्वास्थ्य और हाइजीन के बारे में भी वे लोगों को जागरूक करती हैं। जोडी के मुताबिक माउंटेन क्लीनर्स का मकसद भारत में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करना और स्कूलों व समुदायों में पर्यावरण शिक्षा तथा रिसाइकिलिंग प्रोग्राम को उत्साहित करना है। इसके साथ-साथ कुछ दीर्घकालिक उद्देश्य भी हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश में रिसाइकिलिंग फैक्टरी के निर्माण के लिए कोष जुटाना और पूरे देश में कचरा प्रबंधन व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अभियान चलाना शामिल हैं। जोडी ने बताया कि जो कचरा वे और उनकी टीम जुटाती हैं, उसमें से 80 फीसद को रिसाइकिल कर दिया जाता है क्योंकि 80 फीसद कचरा प्लास्टिक की बोतलें होती हैं। जो कचरा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है उन्हें धर्मशाला के डंपसाइड में भेज दिया जाता है।

## विकास चंद्रा — गंगा की सफाई

भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा लेकिन दुर्भाग्य से यह सबसे गंदी नदी भी है। हर रोज कचरे और गंदे पानी का रेला इस नदी में बहा दिया जाता है तो वहीं अधजली और अन्य लाशें रोज इस नदी में डाल दिये जाते हैं। गंगा को साफ करने की मुहिम में जुटे हैं विकास चंद्रा जिन्हें स्थानीय लोग गुड्डू बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं। गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए विकास ने पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर कर रखी है। इसके अलावा वे और उनकी टीम रोज गंगा से लाशों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार भी करते हैं। विकास ने गंगा में गंदगी फैलाने वाले लोगों के सामने एक मिसाल कायम की है। हालांकि ऐसे ही नेक काम में जुटी हैं अहमदाबाद की 102 साल की रामा माली। अपने सौवें जन्मदिन पर रामा ने संकल्प लिया कि वे अपने शहर कालूपुर में सफाई के लिए अभियान चलाएंगी और लोगों को कचरा न फैलाने के लिए प्रेरित करेंगी। रामा ने साबित कर दिया है अच्छे काम की शुरुआत के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अब रामा लोगों के बीच परचे बांटती हैं और उनसे कूड़ादान के इस्तेमाल की अपील करती हैं। रामा ने सफाई अभियान की शुरूआत कर अपने चिरयुवा होने का सबूत दिया है।

**गौर कीजिए**

**सुलभ इंटरनेशनल ने पिछले चार दशक में देश में 1.3 मिलियन शौचालयों का निर्माण कराया है।**

रियल हीरो

## सरस्वतीबेन, पुष्पाबेन और मंजुलाबेन — वलसाड

गुजरात के वलसाड जिले की मोती डोलडुंगरी, नारगोल और डांडी पंचायतों में महिलाएं सरपंच के पद पर हैं। इन पंचायतों में पानी की बेहद कमी है जिसके कारण गांव वालों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सरपंच के तौर पर सरस्वतीबेन, पुष्पाबेन और मंजुलाबेन को गांव वालों और खासकर महिलाओं को होने वाली दिक्कतों का अंदाजा था। ऐसे में जब उनके गांव में स्वजल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो इन लोगों ने ठान लिया कि इस कार्यक्रम के जरिये वे अपने गांव को पानी की कमी से निजात जरूर दिलाएंगी।

इस काम में अगर समुदाय का सहयोग नहीं भी मिला तो भी वे पीछे नहीं हटेंगी। मोती डोलडुंगरी में सरस्वतीबेन ने अपने गांव की महिलाओं को योजना के फायदे के बारे में बताना शुरू किया और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से महिलाओं ने 68 हजार रुपये जुटाये और उन योजनाओं को कार्यान्वित कराया जो उनके गांव के विकास के लिए जरूरी थे। इसी तरह नारगोल की सरपंच पुष्पाबेन बरिया के गांव की महिलाओं ने भी चालीस हजार से ज्यादा की रकम जुटाकर योजना के तहत लाभ प्राप्त किया। वलसाड के डांडी गांव में भी पानी की वही दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही थी लेकिन लोगों में एकजुटता के कारण कोई योजना कामयाब नहीं हो पा रही थी। ग्रामीणों ने स्वजलधारा योजना को भी अपनाया लेकिन राशि देने के लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसे में सरपंच मंजुलाबेन टंडेल ने हौसला दिखाया और गांव वालों को प्रेरित कर एक लाख की रकम जुटा ली। आज गांव में पानी की वो कमी नहीं दिख रही जो लोग अब तक झेल रहे थे।

---

## खुशली बाई — चौथिया, बेतूल

भोपाल के बेतूल जिले के चौथिया गांव की सरपंच के प्रयास से खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्ति पाने में बहुत हद तक सफलता पाई जा सकी है। घर में शौचालय मौजूद होने के बाद भी खुले में शौच जाने वाले गांव वालों को समझाने के बाद भी जब कोई असर नहीं हुआ तब सरपंच खुशली बाई ने नये तरीके को अपनाया। जब भी कोई व्यक्ति शौच के लिए खेतों की ओर बढ़ता, पूरे गांव में उसके नाम के साथ गतिविधियों का प्रसारण किया जाने लगता। लिहाजा शर्म के मारे वह व्यक्ति तुरंत घर लौट जाता और अपने घर में मौजूद या सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने लगता।

ऐसा कर पाना सरपंच खुशली बाई के आसान नहीं था। इससे पहले उन्होंने और भी कई उपाय अपनाये लेकिन जब कोई काम नहीं आया तो इस विधि को अपनाने का फैसला किया गया। खुशली बाई के मुताबिक हमने कई उपाय अपनाये। शौच के लिए खेतों में जाने वाले लोगों की तस्वीरें खींच कर उन्हें सार्वजनिक जगहों पर चिपकाने और बच्चों द्वारा बड़े लोगों को समझाने के बाद भी जब गांव वालों ने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो हमने इस तरीके को आजमाने की सोची। इसके लिए महिला-पुरुषों की भागीदारी वाली एक बारह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो खुले में शौच जाने वाले लोगों का पता लगाती थी। टॉर्च और मोबाइल फोन से लैस इन लोगों ने पंचायत भवन में एक कंट्रोल रूम बनाया और खेतों में जाने वाले हर शख्स की जानकारी फोन के जरिये कंट्रोल रूम में देने लगे। इसके बाद इनके नाम को पूरे गांव में प्रसारित किया जाने लगा। इतना ही नहीं इन लोगों पर सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाने लगा। इस तरीके ने लोगों को इतना शर्मिंदा किया कि जल्दी ही उन्होंने खुले में शौच से तौबा कर ली। चौथिया के सभी 238 घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद लोग उसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। हालांकि इसके पहले बेतूल की ही एक युवती अनीता नारे ने शौचालय न होने पर अपना ससुराल छोड़कर अपनी शादी को दांव पर लगा दिया था फिर भी आम लोग इसका महत्व समझना नहीं चाहते थे। तब एक महिला सरपंच के प्रयासों ने चौथिया गांव के लोगों को सबक सिखाना जरूरी समझा।

---

## बेकियाम — तमिलनाडु

तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के पल्लनदानपट्टी पंचायत में आपको ऐसी महिलाएं दिख जाएंगी जिनका काम पूरे गांव में घूम-घूम कर लोगों को सफाई के महत्व के बारे में समझाना और सफाई के सही तरीके के बारे में बताना है। ऐसे ही काम में जुटी है बेकियाम। एक-एक व्यक्ति के पास जाना और उन्हें सफाई और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना कोई आसान काम नहीं है। वो न केवल गांव वालों को शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी देती है बल्कि उन्हें सफाई के तरीके के बारे में भी बताती हैं। मात्र एक हजार रुपये या उससे भी कम मासिक के लिए ये महिलाएं दिन भर बस चलती और लोगों से बात करती रहती हैं। अब तो ये महिलाएं गांवों में खासी लोकप्रिय भी हो गई हैं। कभी अकेले तो कभी समूह में ये कहीं भी पहुंच जाती हैं और लोगों को सफाई व हाइजीन के बारे में बताने लगती हैं। लोग अब इनकी बातों पर यकीन भी करने लगे हैं और शौचालय निर्माण के लिए मौजूद विकल्पों के बारे में इनसे पूछने लगे हैं। इतना ही नहीं स्कूलों में बच्चों के बीच जाकर खेल-खेल में और नाच-गाकर ये उन्हें शौचालय का महत्व बताती हैं। इसके लिए वे कई बार अपने साथ लाये हुए चार्ट और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का भी इस्तेमाल करती हैं।

**गौर कीजिए**

**2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि देश के प्रत्येक सरकारी स्कूल में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।**

रियल हीरो

## मइरादा — फेडरेशन ऑफ वुमेन

केरल के इरोड जिले में स्वयंसेवी संगठन मइरादा ने महिलाओं के माइक्रोक्रेडिट समूहों को मिलाकर एक फेडरेशन का निर्माण किया है। यह फेडरेशन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से अपने सदस्यों के लिए शौचालय व अन्य स्वच्छता संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। संगठन के भीतर ही महिला सदस्य शौचालय निर्माण के लिए कर्ज लेती हैं और जब वो पैसे वापस करती हैं तो उसी पैसे को फिर किसी अन्य महिला सदस्य को कर्ज के तौर पर दे दिया जाता है। सदस्यों को बिना ब्याज के कर्ज मिलता है और यह क्रम चलता रहता है जबकि मूल धन फेडरेशन के विकास के काम में लगाया जाता है। फेडरेशन की खूबी यह है कि फंड के लेन-देन का पूरा काम महिला सदस्य ही संभालती हैं जबकि मइरादा केवल ऑडिट की जिम्मेदारी को संभालता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद न केवल महिलाओं को स्वच्छता के लिए जागरूक बनाना है बल्कि इस काम के प्रबंधन और संचालन के जरिये संस्था को चलाने के लिए जिम्मेदार बनाना भी है।

## डीडीएसएस — मेदिनीपुर

देश में पहली बार मांग आधारित स्वच्छता नीति (डीडीएसएस) को पश्चिम बंगाल और सरकार और मेदिनीपुर जिला परिषद के सहयोग से मेदिनीपुर में 1990 में अपनाया गया था। इसे रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद और यूनिसेफ ने मिलकर शुरू किया था। मेदिनीपुर में शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट इस समय देश के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। जितने भी तरीके और रणनीतियां मेदिनीपुर में अपनाये गये लगभग सभी को केंद्र सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए भी अपनाये हैं। मेदिनीपुर में किये गये एक हालिया सर्वे में पाया गया कि जिले के 72 फीसद घरों के लोग अपने यहां मौजूद शौचालय को और बेहतर बनाना चाहते हैं। 38 फीसद लोग अपने शौचालय में सेरामिक का फर्श लगवाना चाहते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट का मकसद सामाजिक जागरूकता के जरिये लोगों में स्वच्छता का प्रसार करना था। इसके लिए उनके सामने शौचालय के कई विकल्प रखे गये। हर ब्लॉक में सैनिटरी मार्ट और उत्पादन केंद्र बनाये गये। इस काम में एनजीओ और अन्य सरकारी-प्राइवेट एजेंसियों को भी लगाया गया। तमाम उपायों और सरकार के सहयोग के बाद सौ फीसद सफलता पाई जा सकी। यूनिसेफ के एक अध्ययन में पाया गया कि 19 गांवों के 96.73 फीसद परिवारों ने अपने घरों में शौचालय बनवाये क्योंकि सुविधाएं उनके दरवाजे तक पहुंचाई गई थीं। कम लागत वाले शौचालय बनवाने वाले 85.62 फीसद परिवार भी संतुष्ट दिखे और उन्हें शौचालय से कोई समस्या नहीं आई। वर्ष 2001 में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम ब्लॉक दो देश का पहला ब्लॉक बना जहां के सौ फीसद घरों में शौचालय बनवाये गये।

## स्वयं सहायता समूह — कोरापुट

उड़ीसा देश में सबसे कम शौचालयों वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाकों में केवल 14.1 फीसद घरों में ही शौचालय की सुविधा है जबकि 84.7 फीसद लोग खुले में शौच के लिए मजबूर है। राज्य का कोरापुट जिला देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है और यहां केवल 8.2 फीसद घरों में ही शौचालय मौजूद है। वर्ष 2010 में यूनिसेफ द्वारा कराये गये एक अध्ययन में पाया गया कि शौचालय बनवाये जाने के बाद भी यहां के लोग उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि वे खुले में शौच की अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहते। इस अध्ययन के बाद जरूरत थी पूरे समुदाय को लामबंद करने की। वर्ष 2001 में उड़ीसा सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जाना था ताकि वे अपने विकास के लिए योजनाओं को चलाने के लिए खुद प्रेरित हो सकें। कालांतर में सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी मदद देनी शुरू की और उन्हें जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इसके लिए सामुदायिक मंचों, थियेटर, लोक उत्सवों और डोर-टू-डोर अभियान के जरिये लोगों को शौचालय के महत्व को बताया जाने लगा। साथ ही 14 ब्लॉकों मे से हरेक में तीन-तीन स्वयं सहायता समूहों को लगाया गया तथा कुल 42 समूहों को इस काम में लगाया गया जिन्हें 50 -50 हजार की राशि रोटेशन के आधार पर मुहैया कराई गई। इस राशि से 18-20 शौचालयों के निर्माण का काम कराया जाने लगा। इसके लिए समूहों को शौचालय निर्माण में लगे लोगों के साथ प्रशिक्षण दिया गया। पूरे काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया। पूरे काम का नतीजा इस रूप में सामने आया कि मई 2014 तक 46 फीसद घरों में शौचालय बनवाये जा चुके थे। इसके अलावा 98 फीसद स्कूलों और करीब 90 फीसद आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शौचालय बनवाये जा चुके थे। कोरापुट जैसे पिछड़े जिले में ये परिणाम अच्छे अंजाम का संकेत दे रहे थे।

**गौर कीजिए**

**संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि शौचालय निर्माण के साथ-साथ मानसिकता बदलने के उपाय करना ज्यादा कारगर होता है।**

रियल हीरो

## अथुर पंचायत — तमिलनाडु

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के अथुर पंचायत की महिलाएं शौचालय की सुविधा न होने से काफी परेशान थीं। गांव में 866 घर थे लेकिन अस्सी फीसद घरों में शौचालय नहीं होने के कारण सभी को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। महिलाओं को इससे बहुत ज्यादा ही असुविधा होती थी। ज्यादातर महिलाएं यहां मजदूर और कुली के रूप में काम करती थीं। जब गांव की सरपंच एक महिला बनी तो महिलाओं ने उनसे शौचालय बनवाने की मांग की। इस काम में सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की। गांव वाले मजदूर के रूप में काम करने के लिए तैयार थे लेकिन पैसा किसी के पास नहीं था। सरकार की ओर से 1200 रुपये शौचालय बनवाने के लिए सब्सिडी के तौर पर दिये जाते थे लेकिन इतना काफी नहीं था। बाकी राशि के लिए उन्होंने पंचायत के धनी लोगों से मदद लेने का फैसला किया लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब सरपंच ने सुझाव दिया कि गांव के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जो राशि जमा की गई है क्यों न उसे ही शौचालय निर्माण में लगा दिया जाय। गांव वालों ने इस सुझाव को पसंद किया। इस तरह सरकारी सब्सिडी, कुछ छोटी कंपनियों की मदद और मंदिर के लिये रखे गये पैसे से शौचालय निर्माण का काम शुरू किया गया। पहले चरण में तीन सौ घरों में शौचालय बनवाये गये और हरेक के लिए एक हजार रुपये का बजट रखा गया। काम शुरू हो गया और इसमें कामयाबी भी मिलती गई। इतना ही नहीं गांव वालों ने गांव की हर गली में कचरा पेटी भी बनवाई ताकि गंदगी से बचा जा सके। इस तरह सरपंच की सूझ-बूझ और प्रयासों से लोगों को खुले में शौच के लिए जाने से छुटकारा मिल सका।

## सचिन्द्र नगर कॉलोनी — त्रिपुरा

पश्चिमी त्रिपुरा के जिरनिया ब्लॉक स्थित सचिन्द्र नगर कॉलोनी पंचायत को राष्ट्रीय ग्राम पंचायत के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2001-02 में जब देश में संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी तो उस समय इस पंचायत के एक भी घर में वैज्ञानिक शौचालय नहीं था। अभियान शुरू होने के बाद ग्राम पंचायत ने लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों के हौसले का नतीजा यह निकला कि महज तीन साल बाद ही 2005 में पंचायत को राष्ट्रीय सम्मान मिल गया। बीपीएल बहुल इस पंचायत में यह सब बहुत आसान नहीं था। सभी घरों में शौचालय बनाए जाने के बाद भी लोगों को उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल काम था। इसके लिए पंचायत ने अनोखा तरीका निकाला। यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ पाया गया तो पंचायत में बुलाकर उससे ऐसा करने का कारण पूछा जाएगा। अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उसका कार्टून बनाकर बाजार में चिपका दिया जाएगा। इस उपाय का बहुत अच्छा परिणाम सामने आया। त्रिपुरा सरकार के पीडब्ल्यूडी के पेयजल और स्वच्छता विंग के मुताबिक जब से पंचायत ने यह फरमान सुनाया तब से पंचायत में एक भी व्यक्ति के खुले में शौच करने का मामला सामने नहीं आया है। गांव वालों ने इसके बाद अन्य क्षेत्रों में सोचना शुरू किया जिससे गांव का पूरा विकास हो पाया। वर्तमान में इस पंचायत में एक उच्च विद्यालय और तीन मध्य विद्यालय हैं। इसके अलावा एक आंगनबाड़ी केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, बाजार और पंचायत कार्यालय भी हैं। ग्रामीणों ने इस बात को समझा कि एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज ही विकास की ओर बढ़ सकता है।

## वॉश — वर्ल्ड विजन

स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे वर्ल्ड विजन को बड़ी कामयाबी मिल पाई है। विशेषकर केबु प्रांत के उन क्षेत्रों में जहां हेयान तूफान से भारी तबाही हुई, वर्ल्ड विजन ने लोगों की हाइजीन का खास ध्यान रखा। तूफान प्रभावित इलाकों में जिन दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी भोजन और मकान बनाने की सामग्री। ऐसे में साफ-सफाई की सामग्रियों, साबुन और टूथपेस्ट जैसी चीजों की ओर तो किसी का ध्यान तक नहीं जाता था। तब लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए वर्ल्ड विजन ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें साफ-सफाई की चीजें बांटनी शुरू की। इसका लोगों और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ा।

वर्ल्ड विजन के वाटर, सैनिटशन और हाइजीन (वॉश) प्रोग्राम के तहत बागे के गांवों में एक हजार से ज्यादा परिवारों के बीच हाइजीन किट का वितरण किया गया। इस किट में नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हाथ धोने का साबुन, सैनिटरी नैपकिन और अंडरयिवर मौजूद होते थे। वॉश हाइजीन प्रमोशन ऑफीसर शेरिल एना रोसेल्स ने कहा कि लोगों के सामने सबसे पहली प्राथमिकता भोजन का जुगाड़ करने की थी। उनके पास जो भी पैसे होते थे वे उसे भोजन खरीदने में लगाते थे। ऐसे में हाइजीन का सवाल ही नहीं उठता था। तब हमारे प्रोग्राम के तहत हमने लोगों को चीजें बांटने से पहले अपने शरीर की सफाई के बारे में लोगों को बताया और उन्हें सफाई के सही तरीके भी सिखाये। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी सफाई के तरीके के बारे में नहीं जाना था।

**गौर कीजिए**

**पश्चिमी अफ्रीका में इस साल फैले इबोला संक्रमण के पीछे गंदगी और खुले में शौच बड़ा कारण रहा।**

रियल हीरो

## वाटरएड — एनजीओ

वाटरएड एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जिसका निर्माण वर्ष 1981 में यूनाइटेड नेशन द्वारा आहूत अंतरराष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक (1981-1990) के दौरान इंग्लैंड में किया गया था। वर्तमान में यह भारत सहित 27 देशों में काम कर रहा है। भारत में यह संगठन स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर स्थायी एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और हाइजीन के लिए कम बजट वाले उपायों की तलाश और प्रसार के काम में जुटा है। इसका मकसद हर व्यक्ति को पानी और शौचालय की सुविधा मुहैया कराना है।

भारत में यह संगठन वर्ष 1986 से काम कर रहा है। इस समय यह दस राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अपनी कार्यक्रमों को चला रहा है। इन राज्यों के पिछड़े और कम विकसित इलाकों में लोगों को शौचालय और सफाई के महत्व को समझाने के साथ-साथ ये उन्हें कम बजट वाले शौचालयों के निर्माण के लिए उत्साहित भी करता है। शौचालयों के रख-रखाव और सफाई के सही तरीके के लिए यह लोगों को प्रशिक्षण भी देता है। गंदगी और खुले में शौच से होने वाली बीमारियों और आजीवन नुकसान के बारे में बताकर वाटर एड लोगों से गंदगी मिटाने और सफाई अपनाने की अपील करता है। इसके अलावा यह संगठन स्थानीय समूहों के साथ मिलकर तटीय इलाकों में साफ पानी की व्यवस्था करने में भी जुटा है। इसके लिए यह नई तकनीकों के इस्तेमाल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। वर्षा के पानी के संग्रहण और पानी से लवण को निकालकर उन्हें पीने योग्य बनाने के काम में भी यह संगठन लगा हुआ है।

## इंडिया सैनिटेशन पोर्टल — ऑनलाइन पहल

इंडिया सैनिटेशन पोर्टल भारत में स्वच्छता अभियानों के बारे में जानने का ऑनलाइन दरवाजा है। इस दरवाजे में घुसते ही देश में स्वच्छता की स्थिति और स्वच्छता अभियानों की प्रगति का लेखा-जोखा सामने आ जाता है। आम लोगों और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए यह जानकारी इकट्ठा करने का साझा मंच है। इस वेब पोर्टल का मकसद सैनिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के अनुभव, उनकी जानकारियों और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पूरी सूचना इकट्ठा करना और फिर उसे इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ-साथ यह सफाई के लिए लोगों के बीच जागरूकता के प्रसार और उनमें सफाई की आवश्यकता को समझने की आदत को भी विकसित करता है। सूचनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपनी समर्थता के कारण ही आज इंडिया सैनिटेशन पोर्टल एक आंदोलन चला पाने में कामयाब रहा है। इस वेब पोर्टल को नवम्बर, 2008 में तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जारी किया था।

## युनिसेफ — संयुक्त राष्ट्र

विकासशील देशों में बच्चों तक मौलिक सुविधाओं और अधिकारों तक पहुंचाने में यूनिसेफ का बड़ा हाथ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था ने स्वच्छता के लिए भी जो काम किये हैं, वे उल्लेखनीय हैं। भारत उन देशों में से एक है, जहां यूनिसेफ ने सफाई के महत्व को समझाने और उसके प्रसार-प्रचार के लिए काम किया है। देश के ज्यादातर राज्यों में यूनिसेफ वहां की सरकार के साथ मिलकर स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को चलाता और कार्यान्वित करता है। लोगों को प्रशिक्षण देना, उनमें साफ रहने और खुले में शौच न करने के लिए जागरूकता फैलाना, बच्चों को पर्यावरण का महत्व समझाना और उन्हें अपने आस-पास गंदगी न फैलाने तथा अपने शरीर की सफाई के लिए प्रेरित करने जैसे काम यूनिसेफ सरकार के साथ मिलकर करता है। बड़ी बात ये है कि यूनिसेफ को इस काम में बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। एक उदाहरण हम असम के पिछड़े इलाके सज्जनपारा का ले सकते हैं जहां के स्कूलों में हाथ धोने और शौचालय जाने की आदत को विकसित कर संस्था ने मिसाल कायम की है। कामरूप जिले के रानी ब्लॉक में स्थित यह गांव बोडो आदिवासियों का क्षेत्र है और यहां लोगों को पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत कम पता था। नतीजतन यहां के बच्चे अक्सर डायरिया और अन्य दूसरी संक्रामक बीमारियों के शिकार रहते थे। लेकिन जबसे यूनिसेफ ने सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एंड सिस्टम (सीएफएसएस) प्रोग्राम चलाया है तब से बच्चों के डायरिया और टायफाइड जैसे रोगों की चपेट में आने के मामले कम हो गये हैं। इस बात को सज्जनपारा प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य सुभानचंद्र बोरो भी मानते हैं। युनिसेफ द्वारा संचालित इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में हाइजीन, सैनिटेशन और पानी के बारे में सही-सही जानकारी पहुंचायी जाती है। इस प्राथमिक विद्यालय के अलावा जिले के 19 और स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाथ धोने के लिए बच्चों को प्रेरित करने वाले इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अब यहां के प्रशासन ने स्कूलों में मिड डे मील में भोजन के साथ-साथ साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्णय लिया है। जाहिर है कि इसका बहुत बड़ा असर बच्चों की आदतों पर भी पड़ेगा और वे केवल हाथ न धोने से होने वाली कई बीमारियों से बच जाएंगे।

**गौर कीजिए**

**खुले में शौच के कारण भारत में होने वाली इक्कीस फीसद बीमारियां पानीजनित होती हैं।**

रियल हीरो

# आध्यात्म और अभियान साथ-साथ

कभी-कभी इंसान को अपनी आदतों को बदलने के लिए भी किसी प्रेरक की जरूरत होने लगती है और जब वह प्रेरणा आध्यात्मिक गुरु की ओर से मिलने लगती है तो उसका असर ज्यादा होता है। लोगों की इस मनोवृत्ति को समझा माता अमृतानंदमयी ने। अम्मा के नाम से प्रसिद्ध माता अमृतानंदमयी ने अपने उपदेशों से लोगों को स्वच्छता और हाइजीन का पालन करने की ओर प्रवृत्त किया है। उड़ीसा में चलाए अपने अभियान के जरिये अम्मा ने वहां की महिलाओं को शौचालय निर्माण के काम में प्रशिक्षित किया है। अम्माची लैब ऑफ अमृता यूनिवर्सिटी में स्थानीय महिलाओं को इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लंबिंग और अन्य मशीनों के उपयोग की जानकारी दी जाती है जिनके इस्तेमाल से महिलाएं शौचालय खुद बनाने और फिट करने में सक्षम हो जाती हैं। अपनी परियाजना के पहले चरण में अम्मा ने राज्य के भोई साही गांव की बीस महिलाओं को बदलाव के एजेंट के तौर पर तैयार किया है जो घरों में शौचालय के पूर्ण निर्माण और उसकी फिटिंग में पारंगत हैं। ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी इस काम में पारंगत होने के लिए प्रेरित करती हैं। इतना ही नहीं ये महिलाएं शौचालय निर्माण के क्षेत्र में निरंतर होने वाले तकनीकी के इस्तेमाल के लिए भी लालायित रहती हैं और कंप्यूटर तक का इस्तेमाल करना जानती हैं। अम्मा के इस प्रयास से उन महिलाओं को लाभ मिला है जो शौच के लिए एक किलोमीटर तक की दूरी तय करती थीं या देर रात घर से बाहर निकलती थीं। अम्माची लैब ने अब तक ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की चार हजार महिलाओं को शौचालय निर्माण के काम में प्रशिक्षित किया है। इसके अलावे लैब ने लाइफ इनरिचमेंट एजुकेशन की भी शुरुआत की है जो सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए महिलाओं को तैयार करता है।

उड़ीसा में खुद शौचालय निर्माण करतीं महिलाएं।

# अपने सम्मान के लिए छोड़ दिया ससुराल

2012 में देश में कुछ अलग और नया हुआ। मध्य प्रदेश की एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के दो दिन बाद ही अपना ससुराल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वहां शौचालय नहीं था। अनीता नारे ने खुले में शौच जाने से इंकार कर अपनी शादी को दांव पर लगा दिया। यह खबर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश में फल गई। असर हुआ और आठ दिन बाद ही उसके पति शिवराम ने अपने बचाये पैसों और पड़ोसियों की मदद से अपने घर में शौचालय बनवा दिया। इसके बाद अनीता अपने ससुराल वापस आ गई। अनीता की इस बहादुरी की पूरे देश में सराहना की गई। आम तौर पर भारतीय घरों में शौचालय को सबसे कम महत्व का और बिना काम का समझा जाता है। खुले में शौच करने की मनोवृत्ति के कारण लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अनीता नारे को सफाई और हाइजीन के महत्व का ज्ञान था और उसने अपने हठ से पति को शौचालय बनाने को मजबूर कर दिया। अनीता के इस काम को सुलभ इंटरनेशनल ने सम्मान देते हुए उसे दस हजार रुपये का इनाम भी दिया। पत्नी के फैसले का सम्मान शिवराम ने भी किया और माना कि शौचालय न होने का सबसे बड़ा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। उन्हें शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है जो सही नहीं है। शिवराम ने कहा कि उसके पास शौचालय बनवाने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन जब पत्नी ने हठ की तो उसने अपने बचाये पैसों और ग्राम परिषद की मदद से शौचालय का निर्माण किया।

सुलभ इंटरनेशनल ने अनीता का किया सम्मान।

**गौर कीजिए**

**वर्ष 1990 के बाद से पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन लोगों को मिली शौचालय की सुविधा।**

रियल हीरो

# सामाजिक उत्तरदायित्व निभा रहा यूनिलीवर

उद्योग जगत को किसी भी देश के विकास की रीढ़ कहा जाता है। वह बीमार हो जाय तो देश की चाल धीमी पड़ जाती है। लेकिन औद्योगिक समूहों की बड़ी जवाबदेही समाज के प्रति भी होती है। अपनी इस भूमिका को बखूबी निभा रहा है यूनिलीवर। सनलाइट प्रोजेक्ट के जरिये यह समूह स्कूली बच्चों और युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ता है। मुंबई और तमिलनाडु के बच्चों को दस हजार यूरो की सहायता देकर यूनिलीवर ने इन बच्चों को अपने शहर की गंदगी को दूर करने के अभियान में लगाया है। मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स की छात्रा 17 साल की मीशा गांधी, मुंबई के ही पवई स्थित एक स्कूल की आठवीं की छात्रा श्रुति एनके और तमिलनाडु के एक स्कूल के नौवीं के छात्र विभिष कश्यप ने इस अभियान से जुड़कर बहुत कुछ जाना-समझा है। मीशा बताती हैं कि अभियान से जुड़ने के बाद जब उन्होंने अपने शहर की स्वच्छता के बारे में जाना तो हैरत में पड़ गईं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे यहां एक शहर के अंदर दो शहर पल रहे हैं। एक जो हर सुविधा से लैस है तो दूसरा वो जो शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से भी महरूम है। दूसरे शहर के लोग सफाई और हाइजीन का मतलब भी नहीं जानते। मीशा ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पानी को संग्रहित रखने का एक उपकरण बनाया है जिससे लोगों को अपने रोज के कामों के लिए पानी ढूंढने की जरूरत न रहे।

कुछ ऐसा ही अनुभव रहा श्रुति का जिन्होंने पाया कि अपने रोज की जरूरत के लिए पानी इकट्ठा करने में भी लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिल्ड्रेन मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस से जुड़कर श्रुति अब घर-घर जाकर लोगों को पानी बचाने और उन्हें साफ व सुरक्षित रखने के बारे में बताती हैं। यूनीलीवर से मिले पैसे से वे किसी ऐसे एनजीओ की मदद करना चाहती हैं जो स्लम एरिया में पानी संरक्षण के उपायों को विकसित करने के काम में लगा हो।

तमिलनाडु के होसुर के एक स्कूल में नौवीं के छात्र विभिष कश्यप जब अपने एक रिश्तेदार के गांव गये तो वहां एक छोटी सी नदी को कचरे से भरा पाया। विभिष को ये गंदगी नागवार लगी। उन्होंने अपने दोस्तों का साथ लिया और उस नदी की सफाई में जुट गये। विभिष के मुताबिक वे पूरी नदी तो साफ नहीं कर पाये लेकिन उनके काम का असर और लोगों पर पड़ा। आखिर हर काम की शुरुआत अकेले ही तो करनी पड़ती है। विभिष ने पानी के लिए लोगों की परेशानी को देखते हुए एक ऐसा बेसिन बनाया है जहां का पानी सीधे शौचालय की टंकी में जाता है और उसका इस्तेमाल फ्लश के लिए किया जाता है। यानी एक ही पानी को दो बार इस्तेमाल करने का बहुत अच्छा तरीका विभिष ने लोगों को दिया है।

# खेल-खेल में पढ़ाया हाइजीन का पाठ

मुंबई की ग्राफिक डिजाइनर एकता अग्रवाल ने अपने कौशल का इस्तेमाल समाज में व्याप्त गंदगी को मिटाने में किया है। सफाई और हाइजीन के प्रति लोगों की मानसिकता को अच्छे से समझने वाली एकता ने डिजाइनिंग का इस्तेमाल कर एक ऐसा हाइजीन किट इजाद किया जो पहले तो बच्चों को और उसके बाद बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। बकौल एकता, 45 मिनट का हाइजीन प्रोग्राम, जिसका नाम मस्ती क्लीन है, बच्चों को खेल-खेल में सफाई का मूल मंत्र बता देता है। इस किट में वर्कशीट, गेम और पढ़ाई के नये तरीके के बारे में बहुत कुछ है।

हाइजीन किट में नेलकटर, साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट और जूं निकालने वाली कंघी होती है। बच्चों में रुचि पैदा करने के लिए सबके नाम भी दिलचस्प रखे गये हैं। जैसे कटर परी, साबुन सफाई, मिस्टर मंजन और मिसेज मनोरंजन तथा मिस्टर इंडिया। विलेन के रूप में जूं को दिखाया गया है और उसका नाम मोगैंबो रखा गया है। सारी चीजों को जिस कार्डबोर्ड के बक्से में रखा गया है, उसे दोबारा मोड़ कर पढ़ाई की टेबुल भी बनाया जा सकता है। अपने अभियान को एकता लैंडर एसोसिएट के तहत चलाती है। उनके मुताबिक यह प्रोजेक्ट हफ्ते दर हफ्ते चलने वाला काम है जो बच्चों को हाइजीन के बारे में बताता है। एकता बताती हैं कि जबसे उन्होंने इस किट को जारी किया है तब से यानी दो साल के भीतर यह सरकारी स्कूलों के दो हजार बच्चों के बीच पहुंच चुका है। इसका असर ये है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति तीस फीसद तक बढ़ गई है। उनके मुताबिक एक बड़ा फर्क जो पड़ा है वो ये है कि बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ गई है क्योंकि किट में शामिल वर्कशीट आकर्षित करने वाले हैं। एकता का यह प्रयास बताता है कि किस तरह अपनी डिजाइनिंग क्षमता का इस्तेमाल कर लोगों को हाइजीन और सफाई के बारे में बताया जा सकता है। एकता को बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने का ध्यान तब आया जब वे बांद्रा में स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाया करती थीं।

**गौर कीजिए**

**दक्षिण एशिया और सब सहारा अफ्रीका के बीस देशों के अस्सी फीसद से ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं।**

रियल हीरो

# लोग गंदगी फैलाते हैं, ये साफ करते हैं

मुंबई के गुरु तेग बहादुर रेलवे नगर, सिओन में स्टेशन पर झाड़ू लगाते और गंदगी साफ करते लोगों का झुंड अक्सर नजर आ जाता है। ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते और न ही इन्हें सरकार ने ऐसा करने को कहा है बल्कि ये लोग अपनी खुशी और लोगों की सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। हर शनिवार को इस समूह के लोग जिसे यूनाइटेड सिख फॉर ह्यूमैनिटी नाम दिया गया है, स्टेशन पर जुटते हैं और लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करते हैं। करीब तीस लोगों का यह समूह दीवार पर पानी की पीक, जमीन पर थूक और अन्य कचरे को साफ करने में जरा भी नहीं हिचकते क्योंकि उन्हें पता है कि सफाई का महत्व क्या है। समूह में काम कर रहे इशमीत सिंह का कहना है कि हमें मालूम है कि गंदगी कितनी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। इसके अलावे यह स्टेशन हमारे धर्मगुरू के नाम पर है तो फिर इसे हम गंदा कैसे देख सकते हैं। पिछले एक महीने से यह काम कर रहे लोगों ने अब आम यात्रियों को जागरूक करने का भी फैसला लिया है। मध्य रेलवे के प्रवक्ता ए.के. सिंह भी इन लोगों के प्रयास की तारीफ करना नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि इस समूह के लोगों के काम से और लोगों को भी सबक लेना चाहिए।

## भारत में मौजूद स्वच्छता नीतियां

1. केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी)
2. राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एनयूएसपी)
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (एनआरएचएम)
4. राष्ट्रीय जल नीति 2102
5. संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी)
6. निर्मल ग्राम पुरस्कार (एनजीपी)
7. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्निर्माण मिशन

# संत गाडगे बाबा की प्रेरणा आई काम

वर्ष 2000 में महाराष्ट्र ने एसजीजीएसए योजना को लागू किया जो महान संत गाडगे बाबा की प्रेरणा से शुरू किया गया था। गाडगे बाबा 19 शताब्दी के एक बड़े संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सफाई के लिए होम कर दिया था। बाबा गाडगे हर रोज गांवों का दौरा करते और गांव में प्रवेश करते ही वे और उनके शिष्य गांव की सफाई करना शुरू कर देते थे। अपने रहने और भोजन के लिए वे पूरी तरह गांव वालों पर निर्भर रहते थे। कहा जाता है कि अपने सिर पर वे हमेशा एक पैन रखते थे और हाथों में झाड़ू। गांव में प्रवास के दौरान रात को वे लोगों के साथ कीर्तन करते थे जिसमें उन्हें साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया जाता और हाइजीन का मतलब समझाया जाता था। अपने पूरे जीवनकाल में वे सफाई के लिए काम करते रहे और इस दौरान कई गीत, लघु नाटक और ऐसे प्रवचन तैयार किये जिनसे लोगों को सफाई और हाइजीन की प्रेरणा मिलती थी। बाबा गाडगे का जीवन महाराष्ट्र के लोगों के लिए हमेशा प्रेरक बना रहा और इसी का फायदा वहां की सरकार ने भी उठाया। यहां के गांवों में एसजीजीएसए योजना को लागू कर वहां स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में हरेक व्यक्ति, युवा, बच्चों और आम लोगों को जोड़ा गया। अभियान के तहत कचरा प्रबंधन और बायोगैस प्लांट निर्माण को भी स्थान दिया गया है। बाबा गाडगे की प्रेरणा का ही असर रहा कि वर्ष 2008-09 में सरोला नाम के गांव को निर्मल गांव पुरस्कार दिया गया। राज्य के तुलजापुर ब्लॉक में स्थित सरोला गांव के युवकों ने योजना का लाभ उठाया और दिन-रात एक कर सफाई अभियान को चलाया। परिणामस्वरूप 2008 में राज्य सरकार ने योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए पुरस्कृत किया।

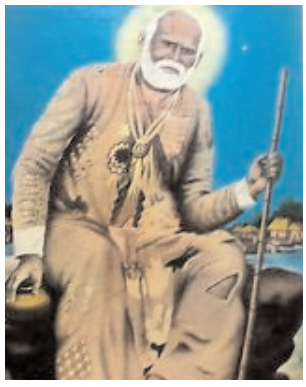

**गौर कीजिए**

**स्वास्थ्य और पानी पर निवेश करने से हर साल 260 बिलियन डॉलर की बचत हो सकती है।**

# मंजरी

स्त्री के मन की

## आगामी अंक

ऑनर किलिंग पर विशेष

---

## अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फॉन्ट का इस्तेमाल करें और **magazinemanjari@gmail.com** पर भेजें। आपके लेख 1000-1500 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। चूंकि हमारा अगला अंक अप्रैल, 2015 में प्रकाशित होगा अतः इसे ध्यान में रखते हुए अपने लेख 25 फरवरी तक भेज दें। आप अपने लेख पत्रिका की वेबसाइट **www.emanjari.com** के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

**मुख्य संपादक**
**नीना श्रीवास्तव**